वर्ष : 34 | अंक : 323 | मुंबई, शुक्रवार, 30 जनवरी 2026 | RNI: MAHHIN/49994/91 | मूल्य : 3 रुपए | epaper.dobajedopahar.com | संपादक : अरुण लाल | संरक्षक : एन. के. पुरोहित

- राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार
- फूट-फूटकर रो पड़े पार्थ और जय, हाथ पकड़कर पिता को दी मुखाग्नि
- भाभी सुनेत्रा को संभालती दिखीं सुप्रिया
- अंतिम यात्रा में उमड़ा जनसैलाब, छतों पर खड़े होकर दादा का आखिरी दीदार
- बारामती में अजित पवार को श्रद्धांजलि देने पहुंचे कई बड़े नेता

DBD
दो बजे दोपहर
पत्रकारिता पावर नहीं रिस्पांसिबिलिटी है

नम आंखों से दी गई 'दादा' को अंतिम विदाई

पंचतत्व में विलीन बारामती का बेटा

बेशुमार भीड़... हर शख्स खामोश... आंखों में आंसू और रुंधे हुए गले... महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन को पैतृक गांव काटेवाड़ी में हर चेहरा शोक में डूबा था। आसपास के इलाकों से लोग पहुंचे थे. बुजुर्गों की कांपती आवाज, महिलाओं की सिसकियां और युवाओं की नम आंखें उस शून्य को बयां कर रही थीं, जो उनके असमय चले जाने से पैदा हुआ है।

एजेंसी । बारामती

गुरुवार सुबह जब उपमुख्यमंत्री अजित पवार के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव काटेवाड़ी लाया गया, तो पूरा इलाका शोक में डूब गया। गांव की गलियों से लेकर उनके आवास के बाहर तक लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। हर आंख नम थी, हर गला रुंधा हुआ और हर जुबान पर एक ही सवाल- क्या वाकई अजित दादा अब नहीं रहे? सुबह होते ही काटेवाड़ी और आसपास के गांवों से लोग पैदल, बाइक और बसों में सवार होकर अजित पवार के घर की ओर निकल पड़े। घर के बाहर लंबी कतारें लग गईं। लोग हाथ जोड़कर, आंखों में आंसू लिए अंतिम दर्शन का इंतजार कर रहे थे। भीड़ के बीच-बीच में नारे गूंज उठते- अजित दादा अमर रहें, अजित दादा परत या।।। इन नारों में सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि एक अपने को खो देने का दर्द साफ झलक रहा था। पार्थिव शरीर को बारामती के पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी अस्पताल से लाकर काटेवाड़ी स्थित आवास पर रखा गया था। जैसे ही अंतिम दर्शन के लिए द्वार खुले, लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। बुजुर्ग महिलाएं रोते हुए जमीन पर बैठ गईं, युवाओं की आंखों से आंसू थे। कई लोग तो बस चुपचाप खड़े थे, जैसे शब्द ही खत्म हो गए हों।

ठहर सा गया पूरा शहर

अंतिम दर्शन के बाद पार्थिव शरीर को बारामती के विद्या प्रतिष्ठान के खेल मैदान ले जाया गया, जहां पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाना था। अंतिम यात्रा जैसे ही शुरू हुई, पूरा शहर ठहर सा गया। हजारों समर्थक सड़कों के दोनों ओर खड़े थे। फूलों से सजा शव वाहन जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा था, वैसे-वैसे "अजित दादा अमर रहें" के नारे पूरे शहर में गूंजने लगे। यह सिर्फ़ एक नेता की अंतिम यात्रा नहीं थी, बल्कि जनता और उनके बीच बने गहरे रिश्ते की आखिरी झलक थी। अंतिम यात्रा के दौरान बारामती का हर इलाका नारों से भर गया। युवा, बुज़ुर्ग, महिलाएं-हर कोई अपने तरीके से अजित पवार को विदाई दे रहा था। किसी की आंखों में आंसू थे, तो कोई हाथ जोड़कर अंतिम दर्शन कर रहा था। "अजित दादा अमर रहें" सिर्फ़ नारा नहीं, बल्कि समर्थकों की भावनाओं की आवाज़ थी। लोगों का कहना था कि अजित पवार ने बारामती ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र के लिए काम किया और यही वजह है कि आज जनता उन्हें अपने परिवार के सदस्य की तरह विदा कर रही है।

राजनीतिक गढ़ से गुजरी अंतिम यात्रा, हर मोड़ पर भीड़

अजित पवार की अंतिम यात्रा उनके राजनीतिक गढ़ बारामती के प्रमुख इलाकों से होकर गुजरी। यह वही इलाक़े थे जहां उन्होंने तीन दशकों से ज़्यादा राजनीति की, चुनाव लड़े और जनता के बीच मजबूत पकड़ बनाई। सड़क किनारे खड़े लोग हाथ जोड़कर श्रद्धांजलि दे रहे थे। कई समर्थक भावुक होकर रोते दिखे। फूलों की बारिश और मौन श्रद्धांजलि के बीच शव वाहन धीरे-धीरे विद्या प्रतिष्ठान मैदान की ओर बढ़ता रहा।

परिवार की मौजूदगी: बेटे जय पवार और रोहित पवार साथ

इस भावुक मौके पर पवार परिवार भी अंतिम यात्रा में साथ दिखाई दिया। अजित पवार के बेटे जय पवार, भतीजे रोहित पवार और परिवार के अन्य सदस्य पूरे समय मौजूद रहे। परिवार के चेहरों पर गहरा दुख साफ झलक रहा था। समर्थक उनके प्रति भी संवेदना जता रहे थे। यह दृश्य बता रहा था कि राजनीति से परे, यह एक परिवार की व्यक्तिगत क्षति भी है, जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। अजित पवार के पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटकर अंतिम यात्रा निकाली गई। यह दृश्य उनके सार्वजनिक जीवन और संवैधानिक पद की गरिमा को दर्शा रहा था। जब शव वाहन विद्या प्रतिष्ठान मैदान की ओर पहुंचा, तो लोगों ने मौन रखकर अंतिम सम्मान दिया। कई समर्थकों ने फूल चढ़ाए और आखिरी बार अपने नेता को नमन किया।

ब्रीफ न्यूज़

यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) के नए नियमों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। CJI सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या की बेंच ने कहा कि इसके प्रावधान स्पष्ट नहीं हैं और इनका गलत इस्तेमाल हो सकता है। कोर्ट ने यह टिप्पणी मृत्युंजय तिवारी, एडवोकेट विनीत जिंदल और राहुल दीवान की याचिकाओं पर की, जिनमें आरोप लगाया गया है कि नए नियम जनरल कैटेगरी के छात्रों के साथ भेदभाव करते हैं। UGC ने 13 जनवरी को अपने नए नियमों को नोटिफाई किया था। इनका देशभर में विरोध हो रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और UGC को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही नियमों का ड्राफ्ट फिर से तैयार करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अगली सुनवाई अब 19 मार्च को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल 2012 के UGC नियम देशभर में लागू रहेंगे।

अब 7 फरवरी को होंगे ज़िला परिषद चुनाव

मुंबई। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के आकस्मिक निधन के कारण राज्य सरकार ने 28 जनवरी से 30 जनवरी 2026 तक तीन दिवसीय राजकीय शोक घोषित किया है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए, राज्य चुनाव आयोग ने 12 जिला परिषदों और 125 पंचायत समितियों के आगामी चुनावों को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। आयोग के अनुसार, शोक की अवधि के दौरान चुनावी प्रक्रियाओं को जारी रखना उचित नहीं था, इसलिए मतदान और मतगणना की पूर्व निर्धारित तिथियों में बदलाव किया गया है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, अब मतदान 5 फरवरी की जगह 7 फरवरी 2026 को आयोजित किया जाएगा। वोटिंग सुबह 7:30 बजे से शुरू होकर शाम 5:30 बजे तक चलेगी। चुनाव प्रचार की समय सीमा भी बदल गई है, जो अब 5 फरवरी 2026 की रात 10 बजे समाप्त होगी। इसके साथ ही, वोटों की गिनती की तारीख को 7 फरवरी से बदलकर 9 फरवरी 2026 कर दिया गया है। मतगणना संबंधित केंद्रों पर सुबह 10 बजे से शुरू होगी और नतीजों की घोषणा के तुरंत बाद आदर्श आचार संहिता हटा ली जाएगी।

मुंबई की जहरीली हवा पर हाईकोर्ट का पारा हाई

निगरानी के लिए बनेगी हाई-पावर कमेटी, रोज होगी समीक्षा

डीबीडी संवाददाता । मुंबई

मुंबई और आसपास के इलाकों में बढ़ते वायु प्रदूषण पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए एक उच्चस्तरीय (हाई-पावर) समिति गठित करने का फैसला किया है। अदालत ने स्पष्ट कहा कि अब तक राज्य और नगर निकायों द्वारा उठाए गए कदम नाकाफी हैं और आम लोगों को शुद्ध हवा में जीने का अधिकार मिलना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि वह किसी पर आरोप नहीं लगा रहा, बल्कि परिणाम सुनिश्चित करना चाहता है।

क्या है अदालत की चिंता?

मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर की अगुवाई वाली खंडपीठ ने कहा कि अक्टूबर 2023 में स्वत: संज्ञान लेने के बाद से हालात में अपेक्षित सुधार नहीं दिखा। नवंबर 2023 में अल्पकालिक, मध्यम और दीर्घकालिक उपाय सुझाए गए थे, लेकिन ज़मीनी असर नजर नहीं आया। दिसंबर में प्रदूषण स्तर "बहुत गंभीर" तक पहुंचने की रिपोर्ट ने अदालत की चिंता बढ़ाई।

अब तक के कदम क्यों नाकाम रहे?

अदालत ने कहा कि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और मुंबई-नवी मुंबई की नगरपालिकाओं की ओर से दाखिल हलफनामे पर्याप्त नहीं हैं। प्रयास किए गए होंगे, लेकिन नतीजे दिखाई नहीं दे रहे। कोर्ट ने यह भी माना कि बढ़ते मामलों और सीमित समय के कारण हर हलफनामे की सूक्ष्म जांच संभव नहीं, इसलिए निगरानी के लिए अलग व्यवस्था जरूरी है।

हाई-पावर कमेटी क्या करेगी?

- समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश करेंगे।
- समिति रोजाना बैठक कर अनुपालन की समीक्षा करेगी।
- नगर निकायों और संबंधित एजेंसियों से प्रगति रिपोर्ट तलब करेगी।
- जरूरी सुविधाएं और अधिकार समिति को दिए जाएंगे, ताकि निर्णय लागू हो सकें।

फरवरी से मुंबई में नए ट्रैफिक नियम

पीक ऑवर्स में लागू होगी यह नई योजना

मुंबई। मुंबई में बढ़ते ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने भारी वाहनों की आवाजाही पर नए प्रतिबंधों का एलान किया है। यह नियम 1 फरवरी से लागू होंगे। पुलिस के अनुसार, पीक ऑवर्स में भारी वाहनों की मौजूदगी से ट्रैफिक धीमा पड़ता है और अन्य वाहन चालकों के लिए जोखिम बढ़ता है।

> "इस आदेश का उद्देश्य पीक ऑवर्स में सड़कों पर दबाव कम करना है। भारी और धीमी गति से चलने वाले वाहन ट्रैफिक रोक देते हैं, जिससे आम लोगों की यात्रा लंबी और परेशानियों भरी हो जाती है।
> **-अमितेश कुमार,** संयुक्त पुलिस आयुक्त (ट्रैफिक)

दक्षिण मुंबई में और सख्त नियम

दक्षिण मुंबई में नियम और भी कड़े किए गए हैं। यहां सभी भारी वाहन, लग्जरी बसों समेत, सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक प्रतिबंधित रहेंगे।

मुंबई कस्टम का तस्करों के खिलाफ कड़ा एक्शन

एक सप्ताह में 35 करोड़ के ड्रग्स, सोना, हीरे और नकदी जब्त

मुंबई। मुंबई कस्टम्स जोन-III ने 21 जनवरी से 29 जनवरी 2026 के बीच छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर तस्करी के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया। इस दौरान एयरपोर्ट कमिश्नरेट की टीम ने अपनी सतर्कता और खुफिया जानकारी के आधार पर ड्रग्स, सोना, हीरे और विदेशी मुद्रा के कई मामले पकड़े। जब्त किए गए इन अवैध सामानों की कुल बाजार कीमत 35 करोड़ रुपये से अधिक आंकी गई है। इस अभियान में सबसे बड़ी सफलता ड्रग्स तस्करी को रोकने में मिली।

रीजेंसी पार्क में वाहन तोड़-फोड़, डेल लैपटॉप चोरी

6 घंटे में आरोपी गिरफ्तार

डीबीडी संवाददाता । कल्याण

कल्याण के चक्कीनाका, रीजेंसी पार्क इलाके में 27 जनवरी 2026 की रात को अज्ञात बदमाशों ने आतंक मचाते हुए सड़क किनारे खड़ी आधा दर्जन गाड़ियों को निशाना बनाया। बदमाशों ने एक आई20 कार (गाड़ी नंबर MH-05 CV-6410) का शीशा तोड़कर उसमें रखा लगभग 18,000 रुपए कीमत का डेल कंपनी का लैपटॉप चोरी कर लिया। इतना ही नहीं, उपद्रवियों ने आसपास खड़ी पांच अन्य वाहनों के भी शीशे तोड़कर उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया। इस मामले में कोळसेवाडी पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई थी।

पुलिस की त्वरित कार्रवाई

वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन में कोळसेवाडी पुलिस की 'गुन्हे प्रकटीकरण पथक' (क्राइम डिटेक्शन टीम) ने सक्रियता दिखाते हुए सीसीटीवी फुटेज और गोपनीय सूचनाओं का सहारा लिया। तकनीकी जांच के आधार पर पुलिस ने घटना के मात्र 6 घंटों के भीतर आरोपी सुजल वाघचौरे (21 वर्ष) को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी किया गया लैपटॉप भी बरामद कर लिया है। इस सफल ऑपरेशन का नेतृत्व सहायक पुलिस निरीक्षक संदीप भालेराव और उनकी टीम ने किया।

मीरा भाईंदर मनपा की भरी तिजोरी

आयुक्त ने ली संपत्ति कर संग्रह की समीक्षा बैठक

डीबीडी संवाददाता । भाईंदर

मीरा भाईंदर नगर निगम (एमबीएमसी) के मुख्यालय में आयुक्त एवं प्रशासक राधाबिनोद शर्मा की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक संपन्न हुई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य समय पर कर भरने वाले नागरिकों को प्रोत्साहित करना, बकाया कर की वसूली में तेजी लाना और वर्तमान कर संग्रह की स्थिति का जायजा लेना था। बैठक में कर विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। कर विभाग से प्राप्त आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 28 जनवरी 2026 की मध्यरात्रि तक कुल 207 करोड़ 28 लाख 47 हजार 806 का संपत्ति कर एकत्र किया जा चुका है। 1,42,781 संपत्ति मालिकों ने डिजिटल माध्यम का उपयोग करते हुए 110 करोड़ 71 लाख 48 हजार 948 जमा किए। 1,32,734 संपत्ति मालिकों ने नकद और चेक के माध्यम से 96 करोड़ 56 लाख 98 हजार 859 का भुगतान किया।

कर वसूली प्रक्रिया को बेहतर बनाने के उपाय

प्रक्रिया को अधिक कुशल और पारदर्शी बनाने के लिए आयुक्त ने अहम निर्देश दिए। क्षेत्रवार विशेष कार्य योजनाएं तैयार की जाएंगी। ऑनलाइन भुगतान सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल मीडिया के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। कर भुगतान की प्रक्रिया को और अधिक सरल और त्वरित बनाने पर जोर दिया गया ताकि नागरिकों को असुविधा न हो। अंत में, सभी संबंधित अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारियों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने और वसूली लक्ष्यों को समय सीमा में पूरा करने का निर्देश दिया गया।

नागरिकों से सहयोग की अपील

आयुक्त राधाबिनोद शर्मा ने शहरवासियों से अपील करते हुए कहा कि शहर में बुनियादी ढांचे, स्वच्छता, जल आपूर्ति, सड़कों, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए संपत्ति कर का समय पर भुगतान अनिवार्य है। नागरिक पूर्ण कर भुगतान कर एमबीएमसी के विकास कार्यों में सहयोग करें।

कर संग्रह की समीक्षा और बकाया पर चर्चा

बैठक के दौरान आयुक्त ने निम्नलिखित बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की। चालू वित्तीय वर्ष में वार्डवार और विभागवार संग्रह की स्थिति और निर्धारित लक्ष्यों के मुकाबले हुई प्रगति की समीक्षा की गई। पिछले वर्षों के बकायादारों की सूची प्रस्तुत की गई। आयुक्त ने स्पष्ट किया कि कर न भरने वालों के विरुद्ध नियमानुसार नोटिस जारी करने, संपत्ति जब्त करने और आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने में कोई ढिलाई न बरती जाए।

नाले की सुरक्षा दीवार गिरी, कोई हताहत नहीं

डीबीडी संवाददाता । ठाणे

आनंद नगर, गांधीनगर स्थित पंचायत सोसाइटी के पास दोपहर लगभग 2 बजे एक गंभीर दुर्घटना हुई, जहाँ नाले की 200 फीट लंबी और 10 फीट ऊंची सुरक्षा दीवार का एक बड़ा हिस्सा ढह गया। मुख्य दीवार गिरने के कारण नाले के किनारे स्थित दो पेड़ अत्यंत खतरनाक स्थिति में आ गए हैं, जिससे पास की सोसाइटी के निर्माण कार्य को सीधा खतरा पैदा हो गया है। आपदा प्रबंधन विभाग को सूचित किए जाने के बाद स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तुरंत सुरक्षा उपाय शुरू कर दिए गए हैं ताकि किसी भी जान-माल के नुकसान को रोका जा सके।

प्रशासनिक मुस्तैदी और राहत कार्य

घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए। घटनास्थल पर नगरसेविका नम्रता भोसले, नगरसेवक राजेंद्र फाटक, और सामाजिक कार्यकर्ता आशुतोष म्हस्के के साथ आपदा प्रबंधन अधिकारी, लोक निर्माण विभाग (PWD) के कार्यकारी अभियंता मोहन कलाल और उनकी टीम उपस्थित थी। फायर ब्रिगेड की टीम भी एक इमरजेंसी गाड़ी के साथ तैनात रही। संबंधित विभागों को इस मामले की लिखित शिकायत भेज दी गई है और अधिकारियों को जल्द से जल्द सुरक्षा दीवार की मरम्मत और खतरनाक पेड़ों को हटाने के निर्देश जारी किए गए हैं।

सिडको अधिकारी और सहायक रिश्वत लेते गिरफ्तार

डीबीडी संवाददाता । नवी मुंबई

नवी मुंबई भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नेरुल स्थित सिडको कार्यालय के प्रभारी सहायक औपनिवेशिक अधिकारी शैलेश आत्माराम घरत (57 वर्ष) को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इस मामले में उनके निजी सहायक नागेंद्र तुलसीराम पांडे (58 वर्ष) को भी हिरासत में लिया गया है। एसीबी के अनुसार, घरत ने शिकायतकर्ता से रिश्वत की राशि अपने सहायक पांडे के जरिए स्वीकार की थी, जिसके बाद ब्यूरो के दस्ते ने जाल बिछाकर दोनों को धर दबोचा और स्थानीय पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया।

होटल में बिछाया गया जाल और गिरफ्तारी

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने योजनाबद्ध तरीके से 28 जनवरी 2026 को नेरुल रेलवे स्टेशन के पास स्थित 'होटल नवमी' में जाल बिछाया। दोपहर करीब 02:38 बजे, जैसे ही सहायक नागेंद्र पांडे ने अधिकारी की ओर से दो लाख रुपए की रिश्वत स्वीकार की, एसीबी की टीम ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके तुरंत बाद मुख्य आरोपी अधिकारी शैलेश घरत को भी हिरासत में ले लिया गया। पुलिस अब इस मामले में आगे की जांच कर रही है ताकि विभाग में फैले भ्रष्टाचार के अन्य पहलुओं का पता लगाया जा सके।

चार लाख की मांग और दो लाख पर समझौता

यह मामला सानपाड़ा स्थित एक घर के सिडको रिकॉर्ड में स्थानांतरण (Transfer) से जुड़ा है। शिकायतकर्ता, जो स्वयं सोसाइटी रजिस्ट्रेशन का कार्य करता है, ने जून 2025 में इसके लिए ऑनलाइन आवेदन दिया था। इस कार्य को पूरा करने के बदले अधिकारी शैलेश घरत ने चार लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। शिकायतकर्ता ने इसकी जानकारी 22 जनवरी 2026 को एंटी करप्शन ब्यूरो को दी। जांच के दौरान शिकायत सही पाई गई, जिसके बाद अधिकारी ने दो लाख रुपए तत्काल देने का दबाव बनाया।

अंबरनाथ सहकारी कृषि समिति को जोर का झटका

210 एकड़ जमीन राज्य सरकार को वापस सौंपने का आदेश

डीबीडी संवाददाता । मुंबई/अंबरनाथ

बॉम्बे हाई कोर्ट ने अंबरनाथ सहकारी कृषि समिति (फार्मिंग सोसायटी) को बड़ा झटका देते हुए 210 एकड़ जमीन राज्य सरकार को वापस सौंपने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति जी.एस. कुलकर्णी और आरती साठे की खंडपीठ ने संस्था की अपील को खारिज करते हुए सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण के निर्णय को बरकरार रखा। इस भूमि का एक बड़ा हिस्सा अब जनहित में सरकारी मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए उपयोग किया जाएगा। राज्य सरकार ने वर्ष 1963 में यह विशाल भूखंड संस्था को खेती, वृक्षारोपण और पर्यावरण संवर्धन के उद्देश्य से निःशुल्क प्रदान किया था। हालांकि, अदालत ने अपने अवलोकन में पाया कि जिस उद्देश्य के लिए भूमि दी गई थी, उसकी शर्तों का गंभीर उल्लंघन किया गया है। कृषि गतिविधियाँ लगभग बंद पाई गईं और सरकारी सहायता से प्राप्त इस भूमि का उपयोग अचल संपत्ति के रूप में व्यावसायिक लाभ के लिए किया जाने लगा।

न्यायालय का सख्त रुख और कानूनी टिप्पणी

उच्च न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि सरकारी भूमि का दुरुपयोग कर उसे 'रियल एस्टेट' की तरह इस्तेमाल करना अस्वीकार्य है और ऐसे कृत्यों को कानूनी संरक्षण नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने सरकार को न केवल जमीन का कब्जा लेने बल्कि सभी अवैध अतिक्रमणों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी पूरी स्वतंत्रता प्रदान की है।

भविष्य की कार्रवाई और हस्तांतरण प्रक्रिया

अंबरनाथ के तहसीलदार अमित पुरी ने स्पष्ट किया है कि उच्च न्यायालय के आदेशानुसार तीन महीने के भीतर भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। वहीं, संस्था के सचिव दीपक पवार ने कहा है कि वे पूर्ण लिखित आदेश मिलने के बाद अपने कानूनी विकल्पों पर विचार करेंगे। प्रशासन अब इस जमीन पर मेडिकल कॉलेज के प्रोजेक्ट को गति देने की तैयारी में है।

निरीक्षण रिपोर्ट में अतिक्रमण का खुलासा

अदालत के समक्ष प्रस्तुत निरीक्षण रिपोर्ट ने संस्था के दावों की पोल खोल दी। रिपोर्ट के अनुसार, 210 एकड़ में से केवल 19 एकड़ भूमि पर ही वृक्षारोपण पाया गया। शेष भूमि पर अवैध मकान, चॉल, दुकानें, शेड और फार्महाउस जैसे लगभग 400 से 500 अतिक्रमण मौजूद हैं। यह भी सामने आया कि संस्था ने मूल किसान सदस्यों को हटाकर संपन्न और गैर-किसान व्यक्तियों को सदस्य बनाया, जो कि नियमों के विरुद्ध था।

संस्था और सरकार की कानूनी दलीलें

संस्था ने बचाव में तर्क दिया कि भूमि पथरीली होने के कारण पूरे हिस्से पर खेती संभव नहीं थी और केवल 97 एकड़ के लिए मिले नोटिस के आधार पर पूरी जमीन जब्त करना गलत है। दूसरी ओर, सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी ने दलील दी कि शहर के बीचों-बीच स्थित इस जमीन का व्यावसायिक दुरुपयोग हुआ है और इसे सार्वजनिक उपयोग के लिए वापस लेना अनिवार्य है।

अजित पवार पर आपत्तिजनक पोस्ट पड़ा भारी

युवक के खिलाफ मामला दर्ज

डीबीडी संवाददाता । मनमाड

एक ओर जहां उपमुख्यमंत्री अजित पवार के आकस्मिक निधन से पूरा महाराष्ट्र शोक संतप्त है, वहीं दूसरी ओर मनमाड के पास धोटाने बुद्रुक गांव में एक युवक की संवेदनहीन हरकत सामने आई है। गणेश कूनगर नामक युवक ने सोशल मीडिया पर अजित पवार के विरुद्ध अपशब्दों का प्रयोग करते हुए एक आपत्तिजनक पोस्ट साझा की। इस घटना ने न केवल स्थानीय लोगों की भावनाओं को आहत किया, बल्कि राजनीतिक हलकों में भी भारी विवाद पैदा कर दिया है।
जैसे ही उक्त पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हुई, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में गुस्से की लहर दौड़ गई। कार्यकर्ताओं ने इस कृत्य को दिवंगत नेता का अपमान बताते हुए तीव्र नाराजगी व्यक्त की। बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता तुरंत पुलिस थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया।

पुलिस कार्रवाई और मामला दर्ज

गुरुकुमार निकाले द्वारा दी गई औपचारिक शिकायत के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी गणेश कूनगर के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 356(3) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। शिकायत दर्ज कराने के दौरान नगरसेवक संतोष अहीरे, योगेश जाधव और अक्षय देशमुख सहित कई अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है ताकि अशांति फैलाने वाले तत्वों पर लगाम कसी जा सके।

एयर होस्टेस पिंकी माली को नम आंखों से दी गई विदाई

डीबीडी संवाददाता । ठाणे

बारामती विमान हादसे का शिकार हुईं 29 वर्षीय एयर होस्टेस पिंकी माली का गुरुवार को मुंबई के शिवाजी पार्क श्मशान घाट में गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार किया गया। उनके पार्थिव शरीर को पहले ठाणे के खारिगांव ले जाया गया और फिर उनके पैतृक निवास प्रभादेवी लाया गया। पिंकी की अंतिम यात्रा में उनके बचपन के दोस्तों, पड़ोसियों और रिश्तेदारों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। जैसे ही उनका शव उनके पुराने घर पहुंचा, पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई और हर आंख नम नजर आई।

भाई के लिए पायलट बनने का सपना

पिंकी के पिता शिवकुमार माली ने अत्यंत दुखी मन से बताया कि उनकी बेटी बेहद महत्वाकांक्षी और परिवार के प्रति समर्पित थी। पिंकी पिछले पांच वर्षों से विमानन क्षेत्र में सक्रिय थीं और उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एअर इंडिया से की थी। उनका एक बड़ा सपना था कि वह अपने बड़े भाई को पायलट बनाएं, जिसके लिए वह लगातार मेहनत और प्रयास कर रही थीं। महज 29 साल की उम्र में उनके निधन से परिवार का एक मजबूत स्तंभ ढह गया है और उनके कई सपने अधूरे रह गए हैं।

वीवीआईपी उड़ानों का शानदार अनुभव

पिंकी माली का पेशेवर करियर काफी प्रभावशाली रहा था। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों और कई दिग्गज राजनेताओं के साथ उड़ानें भरी थीं। उपमुख्यमंत्री अजित पवार के साथ यह उनकी चौथी हवाई यात्रा थी, जो दुर्भाग्यवश उनके जीवन की अंतिम उड़ान साबित हुई। उनके पिता के अनुसार, वे अपने काम में अत्यंत कुशल थीं और चार्टर्ड विमान सेवाओं में उन्हें उनकी विशेषज्ञता के लिए जाना जाता था।

निजी जीवन और अपूरणीय क्षति

पिंकी की शादी तीन साल पहले हुई थी और वह पिछले चार महीनों से ठाणे में अपने पति के साथ रह रही थीं, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी (MNC) में मैनेजर हैं। शिवाजी पार्क में जब उन्हें मुखाग्नि दी गई, तो वहां मौजूद हर शख्स की रूह कांप उठी। इस भीषण विमान हादसे में अजित पवार सहित कुल पांच लोगों की जान चली गई है। पिंकी का जाना न केवल उनके परिवार के लिए बल्कि विमानन जगत के लिए भी एक बड़ी क्षति है, जिसे कभी पूरा नहीं किया जा सकेगा।

हत्या के आरोप में तीन गिरफ्तार

डीबीडी संवाददाता । ठाणे

ठाणे पुलिस की अपराध शाखा ने तत्परता दिखाते हुए 24 घंटे के भीतर महेश नखवा नामक व्यक्ति की हत्या के मामले को सुलझा लिया है। बुधवार को पीड़ित का शव मिलने के बाद ठाणे नगर पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) के तहत मामला दर्ज किया गया था। अपराध शाखा की संपत्ति प्रकोष्ठ ने इस मामले की समानांतर जांच शुरू की, जिसके परिणामस्वरूप तीन आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। वरिष्ठ निरीक्षक गोरखनाथ गर्गे के अनुसार, पुलिस ने घटना के बाद सीसीटीवी फुटेज की सघन जांच की। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस की टीम ने मुंबई-अहमदाबाद राजमार्ग पर स्थित नाइगांव के एक भोजनालय (ढाबे) पर छापा मारा। वहाँ से मुख्य संदिग्ध काली उर्फ रघु चौहान (27) और कवि विनूभाई मंगोलिया (21) को पकड़ा गया। ये दोनों आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए गुजरात भागने की फिराक में थे।

हत्या के पीछे का कारण

पकड़े गए आरोपियों से कड़ी पूछताछ के बाद रघु चौहान की प्रेमिका गीता माली को भी गिरफ्तार कर लिया गया। प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि पीड़ित महेश नखवा कथित तौर पर गीता माली को परेशान कर रहा था। इसी बात से नाराज होकर चौहान और माली ने मिलकर नखवा की चाकू मारकर हत्या कर दी। फिलहाल स्थानीय पुलिस मामले की आगे की कानूनी प्रक्रिया और जांच में जुटी है।

10 फरवरी को चुने जाएंगे महापौर और उप महापौर

डीबीडी संवाददाता । पनवेल

पनवेल महानगरपालिका (PMC) के मेयर और डिप्टी मेयर पदों के लिए आधिकारिक चुनाव 10 फरवरी 2026 को आयोजित किए जाएंगे। कोंकण विभागीय आयुक्त विजय सूर्यवंशी के निर्देशों के अनुसार यह प्रक्रिया संपन्न होगी। पनवेल के नगर आयुक्त मंगेश चितले ने जानकारी दी है कि चुनाव की कार्यवाही सुबह 11 बजे पनवेल शहर के 'आद्यक्रांतिवीर वासुदेव बलवंत फड़के सभागार' में शुरू होगी। रायगढ़ के जिला कलेक्टर किशन जावले को इस चुनावी प्रक्रिया के लिए पीठासीन अधिकारी (Presiding Officer) नियुक्त किया गया है। उनकी देखरेख में ही नामांकन, मतदान और परिणामों की घोषणा की जाएगी। यह चुनाव क्षेत्र की स्थानीय राजनीति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इसके जरिए शहर को नई प्रशासनिक लीडरशिप मिलेगी। सदन में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए भाजपा, शिवसेना और राकांपा (अजित पवार गुट) के महायुति गठबंधन ने गुरुवार को कोंकण विभागीय आयुक्त कार्यालय में आधिकारिक तौर पर अपने समूह का पंजीकरण कराया। इस गठबंधन के पास कुल 59 पार्षदों का समर्थन है। नवनिर्वाचित पार्षदों ने सर्वसम्मति से नितिन जयराम पाटिल को महायुति समूह का नेता चुना है, जो आगामी मेयर चुनाव में अहम भूमिका निभाएंगे।

अंतिम संस्कार स्थल पर बिना अनुमति उड़ाये जा रहे चार ड्रोन जब्त

डीबीडी संवाददाता । बारामती

पुणे जिले के बारामती में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री दिवंगत अजित पवार के अंतिम संस्कार के दौरान वीवीआईपी आवाजाही के समय बिना अनुमति उड़ाए जा रहे चार ड्रोन पुलिस ने जब्त कर लिए। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यह घटना विद्या प्रतिष्ठान कॉलेज मैदान के ऊपर हुई, जहां पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार संपन्न हुआ। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान चार ड्रोन अनधिकृत रूप से उड़ते पाए गए। पहले ड्रोन संचालकों को चेतावनी दी गई, लेकिन कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर पुलिस ने ड्रोन रोधी तकनीक का इस्तेमाल कर सभी ड्रोन गिरा दिए।

सरकार के आश्वासन के बाद किसानों का लॉन्ग मार्च स्थगित

दीपक पवार । मुंबई

नासिक से मुंबई की ओर बढ़ रहे किसानों के विशाल लॉंग मार्च को गुरुवार को सरकार की ओर से मिले लिखित आश्वासन के बाद स्थगित कर दिया गया है। नासिक के जिलाधिकारी आयुष प्रसाद ने शाहपुर-भातसा फाटा इलाके में प्रदर्शनकारी किसानों से मुलाकात की और उनकी मांगों पर शासन स्तर पर हुई सकारात्मक चर्चा की जानकारी दी। प्रशासन के इस हस्तक्षेप और मांगों पर विचार करने के भरोसे के बाद किसानों ने अपना आंदोलन फिलहाल रोकने का निर्णय लिया और अपने गांवों की ओर वापस लौटने लगे।

जल प्रबंधन और सिंचाई संबंधी प्रमुख मांगें

किसानों की मुख्य मांगों में जल वितरण का मुद्दा सर्वोपरि है। गावित के अनुसार, वेस्ट चैनल नदियों की सहायक नदियों पर बांध बनाए जाने चाहिए ताकि खानदेश और मराठवाड़ा के किसानों, उद्योगों और औद्योगिक क्षेत्रों को पर्याप्त पानी मिल सके। साथ ही, अधूरे पड़े बांधों का काम तुरंत पूरा करने और पुराने बांधों से गाद निकालने की मांग की गई है ताकि उनकी भंडारण क्षमता बढ़ सके और खेती के लिए पर्याप्त सिंचाई उपलब्ध हो सके।

जेपी गावित की चेतावनी और तीन महीने की समय सीमा

किसान नेता जेपी गावित ने स्पष्ट किया कि लॉन्ग मार्च को पूरी तरह समाप्त नहीं, बल्कि केवल स्थगित किया गया है। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि अगले तीन महीने के भीतर किसानों की सभी मांगें पूरी नहीं की गईं, तो यह आंदोलन और भी उग्र रूप में दोबारा शुरू किया जाएगा। गावित ने कहा कि सरकार ने सभी मांगों पर सकारात्मक रुख दिखाया है, लेकिन जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन के लिए उन्हें तीन महीने का समय दिया गया है।

वन अधिकार अधिनियम और भूमि स्वामित्व की मांग

आदिवासी किसानों के हितों की रक्षा के लिए फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 के तहत आदिवासियों को 10 एकड़ जमीन तुरंत सौंपने की मांग की गई है। किसानों का कहना है कि सातबारा (भूमि रिकॉर्ड) पर पति और पत्नी दोनों का नाम संयुक्त रूप से दर्ज होना चाहिए। इसके अलावा, वन भूखंड धारकों को कुआं खोदने, जमीन समतल करने, बागवानी और सोलर मोटर जैसी सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ देने और लंबित वन दावों का तुरंत निपटारा करने की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई है।

आर्थिक सुरक्षा, बिजली और शिक्षा संबंधी मुद्दे

किसानों ने अपनी सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गारंटी मांगी है। साथ ही, वन पट्टा धारकों को भी धान की फसल पर 40 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर का बोनस देने की मांग की गई है, जो वर्तमान में आदिवासी विकास विभाग द्वारा दिया जाता है। अन्य मांगों में किसानों को 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति, कृषि क्षेत्र में रिक्त पदों पर तत्काल भर्ती, और ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों व छात्रावासों में शिक्षकों की कमी को दूर करना शामिल है ताकि ग्रामीण छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो।

विमान हादसों की पिछली जांचों पर राऊत ने उठाए सवाल

डीबीडी संवाददाता । मुंबई

शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राऊत ने देश और महाराष्ट्र में हुए पिछले विमान हादसों की जांच को लेकर डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ़ सिविल एविएशन (डीजीसीए) की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उपमुख्यमंत्री अजित पवार की विमान दुर्घटना में हुई दुखद मृत्यु के बाद सुरक्षा चिंताओं को साझा करते हुए राऊत ने पूछा कि अब तक हुए कई चार्टर फ्लाइट और विमान हादसों की जांच का क्या हुआ? उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि अतीत में अहमदाबाद में हुए बोइंग क्रैश और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री की मृत्यु जैसी घटनाओं में भी जांच के आदेश दिए गए थे, लेकिन उनके नतीजे और पब्लिक रिपोर्ट कभी देश के सामने नहीं आई।

डीजीसीए की जिम्मेदारी और चुनावी सुरक्षा

संजय राऊत ने इस बात पर जोर दिया कि चुनाव के दौरान राजनेता अक्सर निजी एयरलाइन कंपनियों की सेवाओं का उपयोग करते हैं। ऐसे में विमान की वैधता, पायलट और तकनीशियनों की योग्यता, तथा सुरक्षा मानकों की बारीकी से जांच करना डीजीसीए की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने चिंता जताई कि अगर सुरक्षा प्रोटोकॉल का सही ढंग से पालन और निगरानी नहीं की जाती है, तो नेताओं और आम नागरिकों की जान जोखिम में बनी रहेगी। उन्होंने मांग की कि विमान सुरक्षा से जुड़ी तकनीकी जांचों को केवल कागजों तक सीमित न रखकर उन्हें सार्वजनिक किया जाना चाहिए।

बारामती हादसे की तकनीकी जांच और ब्लैक बॉक्स

बारामती एयरपोर्ट पर हुए हालिया हादसे का जिक्र करते हुए राऊत ने कहा कि यद्यपि अजित पवार वहां कई बार जा चुके थे, लेकिन कल की घटना में कम दृश्यता एक बड़ा कारण लग रही है। शुरुआती जानकारी के अनुसार, विमान ने दो बार लैंडिंग की कोशिश की थी, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि वह रास्ता भटक गया था। राऊत ने डीजीसीए से तकनीकी खराबी सहित अन्य सभी संभावित कारणों की गहन जांच करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि विमान के ब्लैक बॉक्स से ही असली सच्चाई सामने आएगी कि दुर्घटना के समय असल में क्या हुआ था, बशर्ते इस बार जांच के निष्कर्षों को दबाया न जाए।

मंत्री झिरवाल ने की दोनों एनसीपी को मर्ज करने की मांग

डीबीडी संवाददाता । मुंबई

अजित पवार के उत्तराधिकारी के रूप में उनकी पत्नी और राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार का नाम सबसे आगे चल रहा है। बारामती में अंतिम संस्कार के बाद, पार्टी के दिग्गज नेताओं प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल ने सुनेत्रा पवार से मुलाकात कर उनसे उपमुख्यमंत्री का पद संभालने का आग्रह किया है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि इस कठिन समय में वही पार्टी को एकजुट रख सकती हैं। यदि वे इस प्रस्ताव को स्वीकार करती हैं, तो वह महाराष्ट्र की पहली महिला उपमुख्यमंत्री बनकर इतिहास रच देंगी।

सुनेत्रा पवार को उपमुख्यमंत्री बनाने की मांग

पार्टी के वरिष्ठ नेता और मंत्री नरहरि झिरवाल ने एक महत्वपूर्ण बयान देते हुए शरद पवार और अजित पवार के नेतृत्व वाली दोनों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टियों के विलय (Merge) की जोरदार वकालत की है। झिरवाल का कहना है कि कार्यकर्ता और जनता दोनों ही चाहते हैं कि पवार परिवार के दोनों गुट फिर से एक हो जाएं। उन्होंने जोर देकर कहा कि मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में शक्ति प्रदर्शन के बजाय एकता की अधिक आवश्यकता है, जिससे पार्टी की नींव दोबारा मजबूत हो सके। अन्न व औषधि मंत्री नरहरि झिरवाल के अनुसार, न केवल बारामती बल्कि पूरे राज्य की जनता की यह इच्छा है कि 'भाभी' (सुनेत्रा पवार) सक्रिय राज्य की राजनीति में आएं और पार्टी के सूत्रों को संभालें। पार्टी के कई मंत्रियों का मानना है कि सुनेत्रा पवार को मंत्रिमंडल में शामिल करने से कार्यकर्ताओं में सकारात्मक संदेश जाएगा। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि सुनेत्रा पवार इस बड़ी जिम्मेदारी पर क्या फैसला लेती हैं और क्या शरद पवार गुट इस विलय के प्रस्ताव पर कोई प्रतिक्रिया देता है।

अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार से मिले राकांपा नेता

राकांपा नेताओं ने पवार की पत्नी सांसद सुनेत्रा पवार से मुलाकात की है। इन नेताओं में राकांपा एपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल, महाराष्ट्र प्रदेश राकांपा एपी के अध्यक्ष सुनील तटकरे, वरिष्ठ नेता छगन भुजबल, हसन मुश्रीफ, धनंजय मुंडे, नरहरि जिरवल आदि शामिल थे। इन नेताओं के बीच हुई चर्चा का पता नहीं चल सका है, लेकिन मंत्री नरहरि जिरवल ने कहा कि सुनेत्रा पवार को ही राज्य का उपमुख्यमंत्री पद दिया जाना चाहिए। साथ ही सुनेत्रा पवार को ही पार्टी की भी बागडोर संभालनी चाहिए। जिरवल ने कहा कि पार्टी के अधिकांश नेताओं की यही इच्छा है, लेकिन इसका निर्णय पार्टी को तत्काल लेना चाहिए। हालांकि इस विषय पर राकांपा एपी के नेता प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे ने कोई व्यक्तव्य नहीं दिया।

सांसदों-विधायकों के खिलाफ लंबित मामलों पर कोर्ट सख्त

2 फरवरी को मामले की अगली सुनवाई

डीबीडी संवाददाता । मुंबई

बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को राज्य के विभिन्न जिलों में सांसदों और विधायकों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की धीमी प्रगति पर गहरा असंतोष व्यक्त किया। मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अंखड की पीठ ने विशेष रूप से आरोप पत्र (Charge Sheet) दाखिल न होने पर सवाल उठाए। अदालत ने सरकार से स्पष्ट पूछा कि आखिर इतने समय बाद भी जांच प्रक्रिया पूरी क्यों नहीं हुई है और अब तक कितने मामलों में आधिकारिक तौर पर चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है।

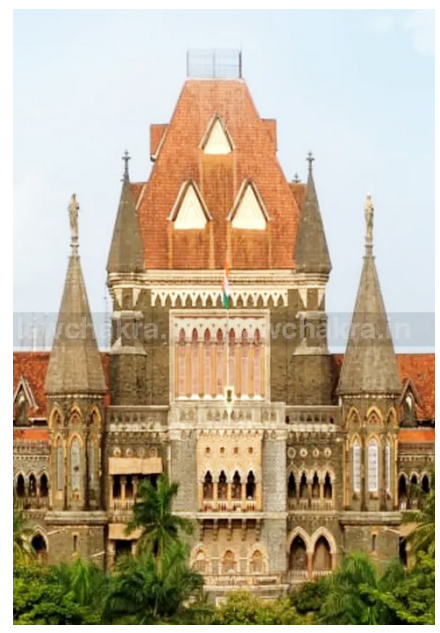

सरकार को एक सप्ताह का अल्टीमेटम

सुनवाई के दौरान जब सरकारी वकील ने बताया कि विभिन्न कारणों से अधिकांश मामलों में अभी तक आरोप पत्र दाखिल नहीं हो सके हैं, तो पीठ ने इसे गंभीरता से लिया। कोर्ट ने राज्य सरकार को कड़ा निर्देश देते हुए एक सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट जमा करने को कहा है। इस रिपोर्ट में सभी लंबित मामलों की वर्तमान स्थिति और आरोप पत्र दाखिल न होने के ठोस कारणों की जानकारी मांगी गई है। इस महत्वपूर्ण मामले की अगली सुनवाई 2 फरवरी 2026 को निर्धारित की गई है।

वीवीआईपी मामले वापस लेने के प्रस्ताव पर रोक

कार्यवाही के दौरान सरकारी वकील ने राज्य न्यायालय प्रबंधन प्रणाली (एससीएमएस) समिति की सिफारिश का हवाला देते हुए तीन हाई-प्रोफाइल आपराधिक मामलों को वापस लेने का अनुरोध किया। इन मामलों में ठाणे के कोलसेवाड़ी पुलिस स्टेशन में दर्ज वह केस भी शामिल है, जिसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे और आनंद परांजपे के नाम हैं। हालांकि, हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए मानहानि से जुड़े एक मामले को वापस लेने की अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया।

महाराष्ट्र में जनप्रतिनिधियों पर दर्ज मामलों के आंकड़े

राज्य सरकार द्वारा अदालत में पेश की गई सूची के अनुसार, महाराष्ट्र भर में वर्तमान में सांसदों और विधायकों के खिलाफ कुल 488 मामले दर्ज हैं। इन आंकड़ों का विश्लेषण करें तो पता चलता है कि अब तक केवल 10 मामलों का पूरी तरह निपटारा हुआ है और महज 47 मामलों में ही आरोप तय किए जा सके हैं। रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया कि इन 488 मामलों में घरेलू हिंसा से जुड़ी शिकायतों को शामिल नहीं किया गया है!

न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाने का प्रयास

जनप्रतिनिधियों से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे के लिए राज्य न्यायालय प्रबंधन प्रणाली (एससीएमएस) समिति सक्रिय रूप से काम कर रही है। अदालत का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रभावशाली पदों पर बैठे व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया में कोई अनावश्यक देरी न हो। वर्तमान में 16 मामलों पर हाई कोर्ट और 5 मामलों पर जिला न्यायालय द्वारा रोक (Stay) लगाई गई है, लेकिन शेष मामलों में अदालत ने पुलिस और प्रशासन को तेजी से आगे बढ़ने के निर्देश दिए हैं।

अजित पवार के निधन के बाद सियासी बयानबाजी तेज

मुंबई। राज्य के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के निधन के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में शोक के साथ-साथ सियासी हलचल भी तेज हो गई है। गुरुवार को अंतिम संस्कार के बाद जहां समर्थक अपने-अपने गांव लौटे, वहीं शिवसेना (उद्धव) सांसद संजय राऊत के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने विवाद खड़ा कर दिया। राऊत ने भाजपा पर निशाना साधते हुए अजित पवार पर लगाए गए कथित 70 हजार करोड़ रुपये के आर्थिक घोटाले के आरोप वापस लेने की मांग की और कहा कि ऐसा करना ही दिवंगत नेता को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। संजय राऊत की पोस्ट पर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि जब पूरा देश अजित पवार के निधन से दुखी है, तब इस तरह के सवाल उठाना विपक्ष की मानसिकता को दर्शाता है।

बृहन्मुंबई महानगरपालिका

विभाग :प्रमुख अभियंता (यांत्रिकी एवं विद्युत)

क्र.कार्य.अभि. यां./4434/प्रशीत दिनांक : 28.01.2026

ई-निविदा सूचना

विषय : रा. ए. स्मा. अस्पताल के शरीर रचना (Anatomy) विभाग में स्थित 200 लीटर क्षमता के डीप फ्रीजर (कोल्ड रूम) को बदलने के संबंध में।

(कार्य.अभि. यां./प्रशि./T-75 दिनांक 28.01.2026)

बोली क्रमांक	2026_MCGM_1272304_1
बोली प्रारंभ होने की तिथि एवं समय	30.01.2026 को प्रातः 11.00 बजे
बोली बंद होने की तिथि एवं समय	05.02.2026 को अपराह्न 04.00 बजे
वेबसाइट	http://portal.mcgm.gov.in http://mahatenders.gov.in
संपर्क अधिकारी का नाम	श्री अ. के. जांभोरे
मोबाइल नंबर	9930128387
ई-मेल	eemechref.me@mcgm.gov.in

हस्ता/-
कार्यकारी अभियंता
यांत्रिकी (प्रशीतन)

पीआरओ/ 2794 / विज्ञा./ 2025-26

समय पर उपचार, बचाएं प्राण।

बृहन्मुंबई महानगरपालिका

(मलनिःसारण प्रचालन विभाग)
ई-निविदा सूचना

ई-निविदा क्रमांक	2025_MCGM_1272053
संस्था का नाम	बृहन्मुंबई महानगरपालिका
विषय	मलनिःसारण विभाग के कार्यकारी अभियंता (यांत्रिकी) (मुख्य मुंबई) पूर्व उपविभाग के कर्मचारियों के लिए विभिन्न सुविधाओं का डिज़ाइन/आराखड़ा तैयार करना, निर्माण, आपूर्ति एवं स्थापना का कार्य।
ई-निविदा छाननी (Processing) शुल्क	1,452 + 18% GST = 1,714/-
कार्यालयीन अनुमान	"आइटम रेट" के आधार पर निविदा
ईएमडी / इसारा राशि	10,000/-
ई-निविदा बिक्री प्रारंभ तिथि	दिनांक 30.01.2026, प्रातः 11:00 बजे से
लिफाफा 'A', 'B' एवं 'C' ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 05.02.2026, अपराह्न 16:00 बजे तक
लिफाफा 'A' एवं 'B' खोलने की तिथि एवं समय	दिनांक 06.02.2026, अपराह्न 16:10 बजे
लिफाफा 'C' खोलने की तिथि	लिफाफा 'A' एवं 'B' की छाननी पूर्ण होने के पश्चात
संपर्क का पता	कार्यकारी अभियंता (यांत्रिकी) (मुख्य मुंबई) पूर्व उपविभाग, पुराना घाटकोपर उंचन केंद्र, शॉपर्स स्टॉप के पास, घाटकोपर-माहुल रोड, घाटकोपर (पूर्व), मुंबई – 400089
लिफाफा 'A', 'B' एवं 'C' खोलने का स्थान	कार्यकारी अभियंता (यांत्रिकी) (मुख्य मुंबई) पूर्व उपविभाग, पुराना घाटकोपर उंचन केंद्र, शॉपर्स स्टॉप के पास, घाटकोपर-माहुल रोड, घाटकोपर (पूर्व), मुंबई – 400089
महाटेंडर पोर्टल	https://mahatenders.gov.in

हस्ता/-
(श्री एस. एल. पाटील)
कार्यकारी अभियंता (यांत्रिकी)
(मु. मुं.),पूर्व उप विभाग

पीआरओ/2798/विज्ञा./2025-26

समय पर उपचार, बचाएं प्राण।

मनपा के 22 स्कूलों में एडमिशन के लिए 4047 आवेदन

मुंबई। मुंबई महानगरपालिका द्वारा संचालित 22 मुंबई पब्लिक स्कूलों में प्रवेश के लिए अभिभावकों ने जबरदस्त उत्साह दिखाया है। इन स्कूलों में उपलब्ध कुल 2,296 सीटों के मुकाबले अब तक 4,047 आवेदन प्राप्त हुए हैं। ये स्कूल न केवल राज्य बोर्ड, बल्कि सीबीएसई, आईसीएसई, आईबी और कैम्ब्रिज जैसे अंतरराष्ट्रीय पाठ्यक्रमों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। आवेदन करने वालों में सबसे बड़ी संख्या नर्सरी कक्षा के लिए है, जो प्री-प्राइमरी स्तर की शुरुआती कक्षा होती है। मनपा शिक्षा विभाग के अनुसार, आवेदनों की जांच के बाद पात्र विद्यार्थियों की पहली सूची 30 जनवरी को जारी की जाएगी। सीटों के आवंटन के लिए पारदर्शी लॉटरी प्रक्रिया 3 से 7 फरवरी के बीच आयोजित होगी, जिसके बाद चयनित छात्रों की अंतिम सूची 9 फरवरी को घोषित की जाएगी। जिन छात्रों का चयन होगा, उन्हें प्रवेश की सभी औपचारिकताएं 11 से 28 फरवरी तक पूरी करनी होंगी।

पश्चिम रेलवे

सामग्री प्रबंधन विभाग

ई-नीलामी बिक्री कार्यक्रम हेतु शुद्धिपत्र (Corrigendum)

फरवरी 2026 के दौरान पी.वे (स्थायी मार्ग) एवं अन्य विभिन्न स्क्रैप के लिए अतिरिक्त ई-नीलामी बिक्री कार्यक्रम

ई-नीलामी बिक्री सूचना सं. **SIII/Auction Programme-1/FEB-2026, दिनांक 07/01/2026** के संदर्भ में यह सूचित किया जाता है कि पी.वे स्क्रैप सामग्री के निपटान हेतु **जनवरी 2026** में आयोजित की जाने वाली निम्नलिखित डिपो के लिए अतिरिक्त ई-नीलामी कार्यक्रम निम्नानुसार रहेगा।

डिपो	जनवरी 2026 का अतिरिक्त ई-नीलामी कार्यक्रम	संभागीय कार्यालय प्रभारी	संपर्क क्रमांक
अहमदाबाद	04.02.2026	वरिष्ठ मंडल सामग्री प्रबंधक – अहमदाबाद	07922205888 0972409375

अन्य सभी नियम एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।
अधिक जानकारी के लिए कृपया **पश्चिम रेलवे** के सामग्री प्रबंधन विभाग की वेबसाइट wr.indianrailways.gov.in तथा www.ireps.gov.in के ई-नीलामी पोर्टल पर अवश्य देखें। **(सं. SIII/Auction Programme-2/FEB 2026, दिनांक 27/01/2026)**

1065

Like us on: facebook.com/WesternRly • Follow us on: X.com/WesternRly

संपादकीय

समानता, आशंका और संतुलन की जरूरत

उच्च शिक्षा किसी भी देश के सामाजिक, आर्थिक और बौद्धिक भविष्य की नींव होती है। इसी व्यवस्था को अधिक समावेशी, न्यायपूर्ण और भेदभाव-मुक्त बनाने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने वर्ष 2026 में नए नियम अधिसूचित किए। इन नियमों का घोषित लक्ष्य उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढावा देना और विशेषकर वंचित वर्गों के साथ होने वाले भेदभाव को प्रभावी ढंग से रोकना था। परंतु इन नियमों के सामने आते ही देशभर में बहस, विरोध और कानूनी चुनौती शुरू हो गई। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इन पर अस्थायी रोक लगाए जाने के बाद यह विषय केवल प्रशासनिक नहीं, बल्कि सामाजिक और संवैधानिक विमर्श का केंद्र बन गया है। यूजीसी के नए नियमों में हर विश्वविद्यालय और कॉलेज में इक्विटी कमेटी और इक्वल ऑपर्च्युनिटी सेंटर को अनिवार्य किया गया। इनका उद्देश्य भेदभाव से जुड़ी शिकायतों को सुनना, उनका निपटारा करना और संस्थानों में समान अवसर का वातावरण बनाना था। यह तथ्य नकारा नहीं जा सकता कि देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था में जाति, वर्ग और सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर भेदभाव के आरोप समय-समय पर सामने आते रहे हैं। कई दुखद घटनाएं इस बात की गवाही देती हैं कि शिकायतों के लिए स्पष्ट और संवेदनशील तंत्र का अभाव रहा है। इस दृष्टि से यूजीसी का यह प्रयास सकारात्मक और आवश्यक प्रतीत होता है। लेकिन किसी भी नीति की सफलता केवल उसके उद्देश्य से नहीं, बल्कि उसके स्वरूप और क्रियान्वयन से तय होती है। नए नियमों को लेकर सबसे बड़ी आपत्ति उनकी भाषा और परिभाषाओं को लेकर उठी। आलोचकों का कहना है कि भेदभाव की परिभाषा अस्पष्ट है और शिकायत की प्रक्रिया में संतुलन का अभाव है। आशंका यह भी व्यक्त की गई कि नियमों का दुरुपयोग संभव है और इससे संस्थानों में भय और अविश्वास का वातावरण बन सकता है। कुछ वर्गों ने यह सवाल भी उठाया कि क्या ये नियम सभी के लिए समान रूप से न्याय सुनिश्चित करते हैं या किसी एक वर्ग तक सीमित हो जाते हैं। इन्हीं चिंताओं के बीच सुप्रीम कोर्ट ने नए नियमों पर रोक लगाते हुए 2012 के पुराने नियमों को फिलहाल लागू रखने का निर्देश दिया। न्यायालय की टिप्पणी इस पूरे विमर्श में महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसने समानता के उद्देश्य को नकारा नहीं, बल्कि नियमों की अस्पष्टता और संभावित दुरुपयोग पर चिंता जताई। यह संकेत करता है कि समस्या उद्देश्य में नहीं, बल्कि प्रस्तुति और संतुलन में है। यह भी सच है कि उच्च शिक्षा संस्थानों को पूरी तरह स्वायत्त और भयमुक्त वातावरण की जरूरत होती है, जहां शिक्षक, छात्र और प्रशासन आपसी विश्वास के साथ कार्य कर सकें। यदि नियम बहुत कठोर या एकतरफा प्रतीत होते हैं, तो वे सुधार के बजाय टकराव को जन्म दे सकते हैं। दूसरी ओर, भेदभाव को नजरअंदाज करना या केवल कागजी व्यवस्थाओं तक सीमित रहना भी गंभीर सामाजिक अन्याय को जन्म देता है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि यूजीसी और सरकार सभी पक्षों से संवाद करें। नियमों की भाषा को स्पष्ट, संतुलित और सर्वसमावेशी बनाया जाए। शिकायत निवारण तंत्र ऐसा हो जो पीड़ित को न्याय दे, लेकिन झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायतों से भी संस्थानों की रक्षा करे। पारदर्शिता, समयबद्धता और निष्पक्षता इन नियमों की आत्मा होनी चाहिए। अंततः समानता केवल नियम बनाने से नहीं, बल्कि विश्वास और संवेदनशीलता से आती है। यूजीसी के नए नियम इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल हो सकते हैं, बशर्ते उन्हें सामाजिक यथार्थ, संवैधानिक मूल्यों और व्यावहारिक संतुलन के साथ दोबारा गढा जाए। सुप्रीम कोर्ट की रोक को टकराव नहीं, बल्कि सुधार के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। तभी उच्च शिक्षा वास्तव में समानता और न्याय का माध्यम बन सकेगी।

समानता की मंशा, पर विभाजन का भय

देवेन्द्र नाथ जैसवार

विरोध करने वालों का एक और महत्वपूर्ण तर्क यह है कि यूजीसी का नया कानून सामाजिक समरसता को मजबूत करने के बजाय जातीय पहचान को और गहरा कर सकता है। भारत पहले ही 78 वर्षों की आजादी के बाद भी जातीय विभाजन से जूझ रहा है। ऐसे में यदि हर समस्या का समाधान केवल जाति के आधार पर खोजा जाएगा, तो समाज के भीतर मौजूद खाइयां और चौडी होंगी। आलोचकों का कहना है कि यह कानून जाति को कमजोर करने के बजाय उसे संस्थागत रूप देता है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा वर्ष 2026 में प्रस्तावित और अधिसूचित नए कानून को उच्च शिक्षा में समानता, न्याय और भेदभाव के उन्मूलन की दिशा में एक बडा कदम बताया गया। इसका उद्देश्य यह था कि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में जाति, वर्ग या सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर होने वाले भेदभाव को रोका जाए और वंचित वर्गों को सुरक्षित, सम्मानजनक वातावरण मिल सके। लेकिन जैसे ही यह कानून सार्वजनिक हुआ, इसके खिलाफ देशभर में विरोध के स्वर तेज हो गए। छात्रों, शिक्षकों, शिक्षाविदों और सामाजिक संगठनों ने इसे समानता का माध्यम नहीं, बल्कि नए प्रकार के सामाजिक और शैक्षणिक विभाजन का कारण बताया। यह विरोध केवल भावनात्मक नहीं, बल्कि गंभीर तर्कों और आशंकाओं पर आधारित है।

यूजीसी के नए कानून के विरोध का पहला और सबसे मजबूत आधार उसकी भाषा और परिभाषाएं हैं। आलोचकों का कहना है कि भेदभाव की परिभाषा न तो स्पष्ट है और न ही संतुलित। कानून में जाति आधारित भेदभाव को केंद्र में रखा गया है, लेकिन शिक्षा संस्थानों में होने वाले अन्य प्रकार के भेदभाव—जैसे वैचारिक मतभेद, अकादमिक असहमति या प्रशासनिक टकराव—को लेकर स्थिति अस्पष्ट है। जब किसी कानून की भाषा व्यापक व्याख्या की गुंजाइश छोड देती है, तो उसके दुरुपयोग की आशंका स्वाभाविक रूप से बढ जाती है। विरोधियों का तर्क है कि इस कानून के तहत किसी भी सामान्य अकादमिक निर्णय को भी जातीय भेदभाव का रूप देकर विवाद खडा किया जा सकता है।

दूसरी बडी चिंता यह है कि यह कानून शिक्षा संस्थानों के भीतर भय और संदेह का वातावरण बना सकता है। हर विश्वविद्यालय में इक्विटी कमेटी और शिकायत निवारण तंत्र को अनिवार्य किया गया है। सैद्धांतिक रूप से यह व्यवस्था सही लगती है, लेकिन व्यवहार में इसके प्रभाव को लेकर शंका है। शिक्षकों का

कहना है कि वे अब छात्रों का मूल्यांकन, अनुशासन या अकादमिक मार्गदर्शन करते समय हर कदम पर शिकायत की आशंका से घिरे रहेंगे। इससे न केवल शिक्षण की स्वतंत्रता प्रभावित होगी, बल्कि गुरु-शिष्य संबंधों की सहजता और विश्वास भी कमजोर पडेगा। शिक्षा संवाद और विचारों के आदान-प्रदान से फलती-फूलती है, न कि डर के माहौल में।

विरोध करने वालों का एक और महत्वपूर्ण तर्क यह है कि यूजीसी का नया कानून सामाजिक समरसता को मजबूत करने के बजाय जातीय पहचान को और गहरा कर सकता है। भारत पहले ही 78 वर्षों की आजादी के बाद भी जातीय विभाजन से जूझ रहा है। ऐसे में यदि हर समस्या का समाधान केवल जाति के आधार पर खोजा जाएगा, तो समाज के भीतर मौजूद खाइयां और चौडी होंगी। आलोचकों का कहना है कि यह कानून जाति को कमजोर करने के बजाय उसे संस्थागत रूप देता है। संविधान निर्माताओं ने समानता और बंधुत्व की कल्पना की थी, जिसमें समय के साथ जातीय पहचान का प्रभाव कम होता जाए, लेकिन यह कानून उस दिशा के उलट जाता दिखाई देता है।

राजनीतिक संदर्भ में भी इस कानून पर सवाल उठ रहे हैं। कई विरोधी मानते हैं कि जाति आधारित कानून और नियम अक्सर वोट बैंक की राजनीति को पोषित करते हैं। शिक्षा जैसे संवेदनशील और राष्ट्र के भविष्य से जुडे क्षेत्र में यदि राजनीतिक हित हावी होंगे, तो उसका नुकसान सीधे छात्रों और शिक्षकों को उठाना पडेगा। विश्वविद्यालयों को विचार, शोध और आलोचनात्मक सोच का केंद्र होना चाहिए, न कि सामाजिक संघर्ष और राजनीतिक दबाव का अखाडा। आरोप यह भी है कि यूजीसी ने इस कानून को बनाते समय व्यापक परामर्श और संवाद की प्रक्रिया को नजरअंदाज किया।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा यूजीसी के नए कानून पर अस्थायी रोक लगाए जाने को भी विरोधियों के तर्क के समर्थन के रूप में देखा जा रहा है। न्यायालय ने नियमों की अस्पष्टता और संभावित दुरुपयोग पर गंभीर सवाल उठाए। यह संकेत है कि समस्या केवल सामाजिक असंतोष की नहीं, बल्कि संवैधानिक और कानूनी संतुलन की भी है। जब सर्वोच्च न्यायालय यह मानता है कि नियमों में स्पष्टता की कमी है, तो यह सरकार और यूजीसी दोनों के लिए आत्ममंथन का अवसर होना चाहिए। विरोध करने वाले यह भी स्पष्ट करते हैं कि वे भेदभाव के खिलाफ नहीं हैं। उनका कहना है कि भेदभाव एक वास्तविक और गंभीर समस्या है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन इसका समाधान जल्दबाजी में बनाए गए कठोर और एकतरफा कानूनों से नहीं होगा। इसके लिए संवेदनशील प्रशासन, नैतिक शिक्षा, सामाजिक संवाद और पारदर्शी व्यवस्था की जरूरत है। यदि समाज की सोच में परिवर्तन नहीं आएगा, तो कोई भी कानून केवल कागजों तक सीमित रह जाएगा और व्यवहार में तनाव बढाएगा।

अंततः यूजीसी के नए कानून का विरोध इस बात का संकेत है कि समाज समानता चाहता है, लेकिन विभाजन की कीमत पर नहीं। शिक्षा का उद्देश्य समाज को जोडना, विचारों को मुक्त करना और नागरिकों को जिम्मेदार बनाना है। यदि कोई कानून इस उद्देश्य से भटकता हुआ प्रतीत होता है, तो उसका विरोध स्वाभाविक और लोकतांत्रिक है। आवश्यकता इस बात की है कि यूजीसी इस कानून पर पुनर्विचार करे, सभी हितधारकों से संवाद करे और ऐसे संतुलित नियम बनाए, जो न्याय भी दें और समाज को बांटें नहीं। तभी उच्च शिक्षा वास्तव में राष्ट्र निर्माण की मजबूत नींव बन सकेगी।

जीवन मंत्र

शरीर और आत्मा : जीवन की संतुलित यात्रा

आज का मनुष्य अक्सर शरीर पर अत्यधिक ध्यान देता है। सुंदरता, शक्ति, सुविधा और भोग की दौड में वह यह भूल जाता है कि शरीर साधन है, साध्य नहीं। जब शरीर को ही सब कुछ मान लिया जाता है, तब थकान, तनाव और असंतोष जन्म लेते हैं।

मानव जीवन शरीर और आत्मा के अद्भुत समन्वय से बना है। शरीर हमें इस संसार में कर्म करने का माध्यम देता है, जबकि आत्मा हमें चेतना, संवेदना और उद्देश्य प्रदान करती है। शरीर दृश्य है, नश्वर है, समय के साथ बदलता और क्षीण होता है, वहीं आत्मा अदृश्य, शाश्वत और अजर-अमर मानी गई है। इन दोनों का संतुलन ही सच्चे और पूर्ण जीवन की आधारशिला है। आज का मनुष्य अक्सर शरीर पर अत्यधिक ध्यान देता है। सुंदरता, शक्ति, सुविधा और भोग की दौड में वह यह भूल जाता है कि शरीर साधन है, साध्य नहीं। जब शरीर को ही सब कुछ मान लिया जाता है, तब थकान, तनाव और असंतोष जन्म लेते हैं। इसके विपरीत, आत्मा की उपेक्षा मनुष्य को भीतर से रिक्त कर देती है। आत्मा वह दीप है, जो हमारे विचारों, मूल्यों और विवेक को प्रकाश देता है।

भारतीय दर्शन सिखाता है कि शरीर एक मंदिर है और आत्मा उसमें विराजमान देवता। जिस प्रकार मंदिर की स्वच्छता और देखभाल आवश्यक है, उसी प्रकार शरीर का स्वास्थ्य भी जरूरी है। लेकिन देवता को भूलकर केवल मंदिर की सजावट में उलझ जाना जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता।

योग, संयम और सत्कर्म शरीर को स्वस्थ रखते हैं, जबकि ध्यान, प्रार्थना और सद्विचार आत्मा को पुष्ट करते हैं।

जब शरीर और आत्मा एक दिशा में चलते हैं, तब मनुष्य के

भीतर अद्भुत शक्ति का संचार होता है। कठिन परिस्थितियों में भी वह संतुलित रहता है, क्योंकि उसकी ऊर्जा केवल मांसपेशियों से नहीं, बल्कि आत्मबल से आती है। आत्मा का जागरण ही साहस, करुणा और सेवा का स्रोत है। अंततः जीवन की सफलता केवल भौतिक उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति में निहित है। शरीर का सम्मान करें, उसकी आवश्यकताओं को समझें, पर आत्मा की आवाज को कभी अनसुना न करें। जब हम शरीर की देखभाल के साथ आत्मा का उत्थान करते हैं, तभी जीवन सार्थक, संतुलित और प्रेरणादायक बनता है।

शख्सियत | अमृता शेरगिल

भारतीय कला की आत्मा और साहस की प्रतीक

अमृता शेरगिल भारतीय कला जगत का ऐसा नाम हैं, जिन्होंने कम आयु में ही अपनी प्रतिभा, साहस और दृष्टि से इतिहास रच दिया। उनका जन्म 30 जनवरी 1913 को हंगरी के बुडापेस्ट में हुआ। पिता उमराव सिंह शेरगिल मजीठिया विद्वान और संस्कृत-पारखी थे, जबकि माता मेरी एंटोनेट हंगेरियन गायिका थीं। इस बहुसांस्कृतिक वातावरण ने अमृता की सोच को आरंभ से ही वैश्विक और गहन बना दिया।

अमृता शेरगिल की कला केवल रंगों का खेल नहीं थी, बल्कि वह समाज, स्त्री और जीवन की पीडा को अभिव्यक्त करने का माध्यम थी। उन्होंने यूरोप में रहते हुए पश्चिमी कला की गहरी शिक्षा प्राप्त की। पेरिस के प्रतिष्ठित एकोल दे बो-आर्त में पढाई के दौरान उन्होंने तेल चित्रकला में महारत हासिल की। बहुत कम उम्र में ही उनकी प्रतिभा को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिल गई और उनकी कृतियां यूरोपीय कला जगत में सराही जाने लगीं। इसके बावजूद अमृता का मन भारत की ओर खिंचता रहा। उन्हें लगा कि पश्चिमी कला की तकनीक तब तक अधूरी है, जब तक उसमें भारतीय जीवन की आत्मा न हो। इसी सोच के साथ वे भारत लौटीं। यहां उन्होंने भारतीय ग्रामीण जीवन, स्त्रियों की पीडा, सामाजिक असमानता और साधारण मनुष्य के भावों को अपनी कूची से जीवंत कर दिया। तीन लडकियां, ग्रामीण स्त्रियां, द साउथ इंडियन विलेजर्स जैसी उनकी पेंटिंग्स आज भी भारतीय कला की अमूल्य धरोहर मानी जाती हैं। अमृता शेरगिल का सबसे बडा योगदान यह है कि उन्होंने भारतीय कला को आत्मसम्मान दिया। उस समय जब भारतीय कलाकार पश्चिम की नकल में अपनी पहचान खो रहे थे, अमृता ने भारतीय विषयों को आधुनिक दृष्टि से प्रस्तुत किया। उन्होंने दिखाया कि भारतीय जीवन, रंग, पीडा और सौंदर्य किसी भी अंतरराष्ट्रीय मंच पर कमतर नहीं हैं। उनकी कला में भारतीय दर्शन की गहराई, मानवीय संवेदना और आत्मचिंतन स्पष्ट दिखाई देता है।

अमृता का जीवन साहस और स्वतंत्रता का भी प्रतीक है। उन्होंने सामाजिक रूढियों को चुनौती दी और अपने मन की सुनी। एक स्त्री कलाकार के रूप में उस दौर में स्वतंत्र होकर जीना आसान नहीं था, लेकिन अमृता ने न तो समाज के दबाव को स्वीकार किया और न ही अपनी कला से समझौता किया। उनका जीवन संदेश देता है कि सृजन वही कर सकता है जो भय से मुक्त हो। दुर्भाग्य से अमृता शेरगिल का जीवन बहुत छोटा रहा। मात्र 28 वर्ष की आयु में 1941 में उनका निधन हो गया। इतने छोटे जीवनकाल में उन्होंने जो सृजन किया, वह उन्हें अमर बनाने के लिए पर्याप्त है। आज उनकी कृतियां राष्ट्रीय संग्रहालयों में सुरक्षित हैं और उन्हें आधुनिक भारतीय कला की जननी कहा जाता है।

अमृता शेरगिल का जीवन हमें कई प्रेरणाएं देता है। वे सिखाती हैं कि अपनी जडों से जुडे रहकर भी वैश्विक दृष्टि रखी जा सकती है। वे यह भी बताती हैं कि सच्ची कला वही है, जो समाज के सत्य को निर्भीक होकर सामने रखे। अमृता का संघर्ष, उनका आत्मविश्वास और उनकी कलात्मक ईमानदारी आज भी युवाओं, कलाकारों और विचारकों को प्रेरित करती है।

अंततः अमृता शेरगिल केवल एक महान चित्रकार नहीं थीं, बल्कि वे भारतीय आत्मा की संवाहिका थीं। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि उम्र छोटी हो सकती है, लेकिन विचार और सृजन अनंत हो सकते हैं।

जीवन ऊर्जा

फ्रैंकलिन डी. रूज़वेल्ट : जन्म 30 जनवरी 1882 | जन्म

आर्थिक सुरक्षा के बिना स्वतंत्रता अधूरी है

फ्रैंकलिन डी. रूज़वेल्ट का जन्म 30 जनवरी 1882 को अमेरिका में हुआ। वे अमेरिका के 32वें राष्ट्रपति रहे। महामंदी के दौरान न्यू डील कार्यक्रम से आर्थिक पुनर्निर्माण किया। उनका जीवन दर्शन सामाजिक न्याय, लोकतंत्र की रक्षा और जनकल्याण पर आधारित था।

हमें डरना सिर्फ डर से ही है। लोकतंत्र तभी सुरक्षित है जब जनता जागरूक हो। स्वतंत्रता केवल अधिकार नहीं, जिम्मेदारी भी है। मानव प्रगति का माप यह है कि कमजोर को कितना सहारा मिला। सच्ची उदारता भविष्य में निवेश करना है। आर्थिक सुरक्षा के बिना स्वतंत्रता अधूरी है। एक राष्ट्र की महानता उसकी करुणा से पहचानी जाती है। लोकतंत्र में असहमति भी देशभक्ति होती है। शक्ति का उद्देश्य सेवा होना चाहिए, शोषण नहीं। मानव गरिमा हर नीति की आत्मा होनी चाहिए। शांति केवल युद्ध की अनुपस्थिति नहीं, न्याय की उपस्थिति है। जनता की भलाई सरकार का पहला कर्तव्य है। भविष्य उन लोगों का है जो आशा बनाए रखते हैं। समान अवसर ही सच्चा न्याय है। समाज तभी आगे बढता है जब कोई पीछे न छूटे। लोकतंत्र शब्दों से नहीं, कर्मों से जीवित रहता है। मानव अधिकार राष्ट्रों से बड़े होते हैं। गरीबी स्वतंत्रता की सबसे बड़ी शत्रु है। नेतृत्व का अर्थ है दूसरों को भय से बाहर निकालना। साहस डर की अनुपस्थिति नहीं, उस पर विजय है। सत्ता का नैतिक उपयोग ही सभ्यता की पहचान है। मानव कल्याण बिना नैतिकता के संभव नहीं। सच्ची ताकत सेवा से जन्म लेती है। न्याय जब तक सबके लिए न हो, अधूरा है। लोकतंत्र

जनता की उम्मीदों से चलता है। शोषण किसी भी रूप में सभ्यता के खिलाफ है। सरकार का मूल्य उसके कमजोर नागरिक तय करते हैं। आशा ही मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। शांति का रास्ता मानव गरिमा से होकर जाता है। मानवता की सेवा ही सच्ची राजनीति है। मानव भविष्य करुणा और साहस के संतुलन से बनता है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा दुश्मन निराशा है। जब सरकार जनता के साथ खड़ी होती है, तभी इतिहास आगे बढता है। सच्ची आजादी भय से मुक्ति में है। मानव कल्याण ही राष्ट्र की वास्तविक शक्ति है।

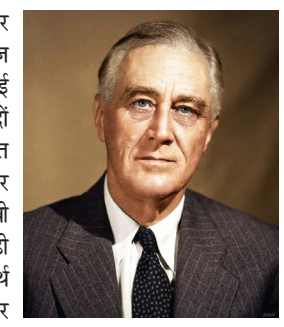

अपने विचार

यह एक अवसर है इसलिए क्वालिटी पर बल दें। इसका असर लंबे समय तक रहता है। यह प्रोडक्टिव भारत की दिशा में बड़ा कदम है। देश का ध्यान बजट की ओर होना स्वाभाविक है। हमारी सरकार की पहचान रही है– रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म और अब हम रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चल पड़े हैं।

–नरेंद्र मोदी
प्रधानमंत्री, भारत

भगवान के लिए ऐसा मत करो। यूजीसी के नए नियम के 3 (सी) (जो जाति–आधारित भेदभाव को परिभाषित करता है) पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हैं और इनका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी भाषा को फिर से बदलने की जरूरत है।

–सूर्यकांत,सीजेआई
सुप्रीम कोर्ट

मैं एक बात बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं कि किसी का उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा। कोई भेदभाव नहीं होगा। यूजीसी, भारत सरकार और राज्य सरकारों की यह जिम्मेदारी होगी। यह मसला तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ही है। मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि किसी के भी साथ अत्याचार नहीं होगा।

–धर्मेंद्र प्रधान
केंद्रीय शिक्षा मंत्री

जातिगत भेदभाव होता है, उस पर गाइडलाइन्स भी होती हैं। लेकिन अगर गाइडलाइन्स ही भेदभाव पूर्ण होंगी... कि आप एक तरफ को सोचे कि यही शोषण कर्ता है और दूसरे तरफ वाले शोषित हैं। यह गलत है। अगर एसएसी एसटी ओबीसी के खिलाफ 10 केस ऐसे आते हैं, तो कुछ केस जनरल कैटेगरी के खिलाफ भी होते हैं।

–प्रियंका चतुर्वेदी
राज्यसभा सांसद

अपने विचार

डीबीडी कार्यालय

ग्राउंड फ्लोर, ऑफिस नं. 2, के.के. चैम्बर्स, पुरुषोत्तमदास ठाकरदास रोड, फोर्ट, मुंबई- 400001

indiagroundreport@gmail.com

भेज सकते हैं।

सर्वसिद्ध श्री बगलामुखी तारा महाशक्ति पीठ बिजाना शाजापुर मध्यप्रदेश

सर्वसिद्ध श्री बगलामुखी तारा महाशक्तिपीठ साधना, शक्ति और सिद्धि का जीवंत केंद्र

भारतीय सनातन परंपरा में महाशक्ति के विविध स्वरूपों की उपासना का जो अद्वितीय और दुर्लभ संगम दिखाई देता है, वही स्वरूप सर्वसिद्ध श्री बगलामुखी तारा महाशक्तिपीठ, बिजानाधाम (शाजापुर, मध्य प्रदेश) में साकार होता है। यह पीठ श्रीकुल एवं कालीकुल की अष्टादश महाविद्याओं का स्वयंभू, जाग्रत और सिद्ध तीर्थ माना जाता है, जहां आद्या शक्ति अनादिकाल से साधकों और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती आ रही

पंडित कैलाशचंद्र शर्मा
वैदिक सनातन संस्कृति के प्रचारक व सर्व सिद्ध श्री बगलामुखी तारा महाशक्ति पीठ के संस्थापक।
मो. नं. 9425980556

हैं। यह महाशक्तिपीठ न केवल धार्मिक दृष्टि से, बल्कि आध्यात्मिक और तांत्रिक साधना की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण यह स्थल अत्यंत शांत, दिव्य ऊर्जा से ओतप्रोत और साधना के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करता है। यहां माता तारा नीलसरस्वती स्वरूप में, उनके साथ माता बगलामुखी तथा माता लक्ष्मी विराजमान हैं। यह त्रिदेवी स्वरूप ज्ञान, शक्ति और ऐश्वर्य का अद्भुत समन्वय प्रस्तुत करता है। इस स्वयंभू पीठ का पुनर्निर्माण विक्रम संवत 2076, शके 1941, फाल्गुन मास, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि को श्री बगलामुखी तारा पीठ के पूज्य गुरुजी के सान्निध्य में संपन्न हुआ। इसके पश्चात यहां विधिवत नित्य पूजन, अनुष्ठान और अर्चन का शुभारंभ हुआ। विशेष रूप से वसंत पंचमी के पावन अवसर पर पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले स्थित तारा पीठ से माता की दो अखंड ज्योतियां, माता की कृपा से भक्त श्री करणजी शास्त्री द्वारा यहां स्थापित की गईं, जिससे इस धाम की आध्यात्मिक गरिमा और अधिक बढ़ गई।

लोकमान्यताओं के अनुसार यह क्षेत्र कुमारिका क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। मान्यता है कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर यहां का पर्वत कुछ समय के लिए स्वर्णमय हो जाता

है। इस क्षेत्र की सिद्ध परंपरा को और अधिक पुष्ट करते हैं आसपास स्थित मनकामनेश्वर महादेव, तक्षक नाग तथा जगत भैरव, जो मात्र 5 से 7 किलोमीटर की परिधि में स्थित हैं। शिव-पार्वती विवाह से जुड़ी अनेक दिव्य स्मृतियां इस क्षेत्र को और भी पावन बनाती हैं। कहा जाता है कि विवाह के समय साल वृक्ष की फूंक आज भी दर्शनीय है तथा जहां-जहां सप्तपदी संपन्न हुई थी, उन सात स्थानों पर आज भी धान के चिह्न श्रद्धालुओं को दिखाई देते हैं। यह स्थल पौराणिक आस्था और जीवंत लोकविश्वास का अद्भुत उदाहरण है। लगभग 500 वर्ष पूर्व यहां श्री जटावाले बाबा माता की सेवा में लीन थे। लोकश्रुति है कि वे आज भी दिव्य रूप में माता की सेवा करते हैं और अनेक श्रद्धालुओं को उनके दर्शन प्राप्त होते हैं। मंदिर के ठीक सम्मुख भैरव जी तथा बाबा श्री नीबकरौरी जी महाराज की दिव्य उपस्थिति इस पीठ की सिद्ध परंपरा को और अधिक सुदृढ़ करती है। साधना की दृष्टि से यह पीठ अत्यंत प्रभावशाली मानी जाती है। यहां माता बगलामुखी तारा के मंत्र जप, अनुष्ठान, हवन और पूजन विधिपूर्वक संपन्न किए जाते हैं। विशेष रूप से शत्रुकृत बाधा निवारण, ऋण एवं रोग नाश, विघ्न शांति, राजयोग प्राप्ति तथा न्याय, राजनीति और चुनाव में विजय हेतु की गई साधनाएं अत्यंत फलदायी मानी जाती हैं।

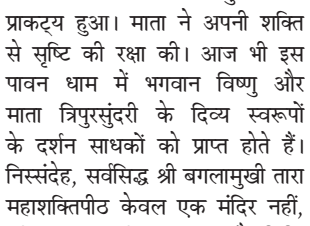

माता बगलामुखी को स्तंभन विद्या की सर्वोच्च महाविद्या और राजयोग की प्रदाता कहा गया है।

मेरु तंत्र के अनुसार, एक समय संसार में उत्पन्न भीषण प्रलयकारी स्थितियों को रोकने हेतु भगवान विष्णु ने आद्या महाशक्ति की आराधना की, जिसके फलस्वरूप माता बगलामुखी का प्राकट्य हुआ। माता ने अपनी शक्ति से सृष्टि की रक्षा की। आज भी इस पावन धाम में भगवान विष्णु और माता त्रिपुरसुंदरी के दिव्य स्वरूपों के दर्शन साधकों को प्राप्त होते हैं। निस्संदेह, सर्वसिद्ध श्री बगलामुखी तारा महाशक्तिपीठ केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि श्रद्धा, शक्ति, साधना और सिद्धि का जीवंत केंद्र है, जहां प्रत्येक भक्त को माता की करुणा और दिव्य अनुकंपा का अनुभूति होती है।

यह अखबार "माध्यम कार्पोरेट सर्विसेज लि. " के लिए प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक अरुण लाल द्वारा ग्राउंड फ्लोर, ऑफिस नं. 2, के. के. चैम्बर्स, पुरुषोत्तमदास ठाकरदास रोड, फोर्ट, मुंबई- 400001 से प्रकाशित एवं सोमानी प्रिंटिंग प्रेस, गाला नं. 4, एन.के.इंडस्ट्रियल इस्टेट, इनसाइड प्रवासी इंडिस्ट्रयल इस्टेट गेट नं. 2, गोरेगांव पू., मुंबई-63 से मुद्रित. फोन नं. 022-66555719 ईमेल : indiagroundreport@gmail.com कार्यकारी संपादक : अमित बृज (पी.आर.बी. अधिनियम के अंतर्गत खबरों के चयन के लिए ज्मिेदार).

ब्रीफ न्यूज़

आध्यात्मिक उत्सव 'संयम रंग उत्सव' का आयोजन

मुंबई। बोरीवली क्षेत्र में अगले सप्ताह एक विशाल आध्यात्मिक उत्सव 'संयम रंग उत्सव' आयोजित किया जाएगा। इस महोत्सव में 18 पुरुष और 46 महिलाएं, कुल 64 मुमुक्षु सांसारिक सुखों का त्याग कर संयम के मार्ग पर कदम रखेंगे और सामूहिक रूप से दीक्षा ग्रहण करेंगे। 'आध्यात्मिक परिवार' और दानदाताओं द्वारा आयोजित यह आध्यात्मिक समारोह 4 फरवरी से शुरू होकर 8 फरवरी को एक भव्य दीक्षा समारोह के साथ संपन्न होगा। इस भव्य आयोजन की तैयारी के लिए बोरीवली के चिक्कूवाड़ी में 2,50,000 वर्ग फुट में फैली एक विशाल 'आध्यात्मिक नगरी' (Township) विकसित की जा रही है। यह अस्थायी नगर पूरी तरह से त्याग, तपस्या, अनुशासन और जैन धर्म के मूल आध्यात्मिक मूल्यों के वातावरण से सराबोर होगा। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को जैन संस्कृति और संयम के जीवन की गहराई को समझने का अवसर मिलेगा। इस समारोह में गच्छाधिपति पूज्य सोमसुंदरसूरीजी महाराज और कई अन्य आचार्यों की गरिमामयी उपस्थिति रहेगी। दीक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया पूज्य शांति चंद्र सूरी परंपरा के जैनाचार्य जिनचंद्रसूरीजी महाराज के शिष्य योगतिलकसूरीजी महाराज के मार्गदर्शन में संपन्न होगी। उल्लेखनीय है कि पिछले एक दशक में योगतिलकसूरीजी के मार्गदर्शन में 50 व्यक्तियों ने दीक्षा ग्रहण की है। इस ऐतिहासिक समारोह में आशीर्वाद देने के लिए 800 से अधिक साधु और साध्वी भी शामिल होंगे।

एक दिन के लिए पुलिस अफसर बना अंश

ठाणे। जन्मजात हृदय रोग से लड़ रहे ठाणे के 10 वर्षीय अंश इंगले ने अपने जन्मदिन से ठीक एक दिन पहले, 26 जनवरी को वाशी पुलिस स्टेशन में 'एक दिन के लिए पुलिस अधिकारी' बनकर अपना सपना पूरा किया। मेक-ए-विश फाउंडेशन और वाशी पुलिस के संयुक्त सहयोग से आयोजित इस पहल ने न केवल अंश को खुशी दी, बल्कि वहां मौजूद हर पुलिसकर्मी को भी प्रेरित किया। वर्दी में सजे अंश का वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शशिकांत चांडेकर और उनकी टीम ने गर्मजोशी से स्वागत किया और उसे सम्मान के साथ वरिष्ठ निरीक्षक की कुर्सी पर बिठाया। एक ड्राइवर के बेटे अंश ने कुछ ही हफ्ते पहले एक जटिल कार्डियक प्रक्रिया — बायलैटरल बिडायरेक्शनल ग्लैन शंट (Glenn Shunt) — करवाई थी। अंश का यह सफल ऑपरेशन श्री सत्य साईं संजीवनी सेंटर फॉर चाइल्ड हार्ट केयर, खारघर के वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. सी.एस. श्रीनिवास द्वारा किया गया था। अभी वह सर्जरी के बाद रिकवरी के दौर से गुजर रहा है, लेकिन उसकी आंखों में भविष्य को लेकर जो चमक और उत्साह दिखा, उसने इस बीमारी की गंभीरता को भी पीछे छोड़ दिया।

पुल कार्य के कारण सफाले केलवे रोड के बीच रेल ब्लॉक

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

पश्चिम रेलवे ने पुल संख्या 114 पर गर्डरों के डी-लॉन्चिंग कार्य के लिए सफाले और केलवे रोड के बीच रेल ट्रैक ब्लॉक की घोषणा की है। यह ब्लॉक 31 जनवरी और 1 फरवरी, 2026 को विभिन्न समयों में लिया जाएगा। अप लाइन पर 31 जनवरी को 02:15 बजे से 03:15 बजे तक तथा डाउन लाइन पर 01:45 बजे से 05:45 बजे तक ब्लॉक रहेगा। 1 फरवरी को अप लाइन पर 00:30 बजे से 04:30 बजे तक तथा डाउन लाइन पर 00:30 बजे से 04:00 बजे तक ब्लॉक लागू रहेगा।

रेगुलेट और रिशेड्युल होने वाली ट्रेनें

सफाले और केलवे रोड के बीच रेल ब्लॉक के कारण 30 जनवरी से 1 फरवरी, 2026 तक कई ट्रेनें रेगुलेट या समय संशोधित होंगी। इनमें 31 जनवरी को विरार–सूरत मेमू (69141) 30 मिनट, बरौनी–बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस (19038) 1 घंटा 30 मिनट, ओखा–मुंबई सेंट्रल मेल एक्सप्रेस (22946) क्रमशः 30 मिनट और 1 घंटा 10 मिनट, भुज–बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्ट (22904) 1 घंटा 30 मिनट, भुसावल–दादर स्पेशल (09052) 50 मिनट, अहमदाबाद–बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस (22928) 45 मिनट, वेरावल–बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस (19218) 45 मिनट, एकता नगर–दादर सुपरफास्ट एक्सप्रेस (12928) 40 मिनट, श्री गंगानगर–बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस (14701) 30 मिनट, अहमदाबाद–दादर एक्सप्रेस (12902) 30 मिनट, इंदौर–मुंबई सेंट्रल सुपरफास्ट (12962) और इंदौर–मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस (09086) 30 मिनट, भगत की कोठी–बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्ट (04827) 30 मिनट, हनुमानगढ़–दादर एक्सप्रेस (14707) 30 मिनट, दहानू रोड–बोरीवली मेमू (69174) 30 मिनट, दादर–एकता नगर सुपरफास्ट (12927) 1 घंटा 20 मिनट, बांद्रा टर्मिनस–जामनगर एक्सप्रेस (22923) 1 घंटा, दादर–भुसावल एक्सप्रेस (19003) 50 मिनट और बांद्रा टर्मिनस–हरिद्वार एक्सप्रेस (19019) 50 मिनट लेट चलेंगी।

प्रभावित ट्रेन सेवाएँ और रद्द ट्रेनें

ब्लॉक अवधि के दौरान कुछ ट्रेन सेवाएँ पूरी तरह निरस्त होंगी। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक के अनुसार, 31 जनवरी, 2026 को दहानू रोड से 07:00 बजे प्रस्थान करने वाली ट्रेन संख्या 93006 (दहानू रोड–विरार मेमू) और 31 जनवरी को विरार से 04:50 बजे प्रस्थान करने वाली ट्रेन संख्या 93001 (विरार–दहानू रोड मेमू) निरस्त रहेंगी। यात्रियों से इस दौरान यात्रा की योजना बदलने की अपील की गई है।

शॉर्ट टर्मिनेट और शॉर्ट ओरिजिनेट ट्रेनें

ब्लॉक के दौरान कुछ ट्रेनें आंशिक दूरी तक ही चलेंगी। 31 जनवरी को प्रस्थान करने वाली ट्रेन संख्या 19101 (विरार–भरूच एक्सप्रेस) केवल पालघर तक चलेगी। इसके चलते यह ट्रेन विरार और पालघर के बीच आंशिक रूप से निरस्त रहेगी। यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना में बदलाव करने की सलाह दी गई है।

गणतंत्र दिवस परेड-2026

महाराष्ट्र की झांकी को मिला पहला स्थान

डीबीडी संवाददाता | मुंबई/नई दिल्ली

देश के 77वें गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर आयोजित परेड में महाराष्ट्र की झांकी को सभी राज्यों की झांकियों में सर्वश्रेष्ठ चुना गया है। इस शानदार प्रदर्शन के लिए महाराष्ट्र को पहला स्थान मिला, जिसकी आधिकारिक घोषणा गुरुवार को की गई। प्रतियोगिता में जम्मू-कश्मीर की झांकी दूसरे और केरल की झांकी तीसरे स्थान पर रही।

'गणेशोत्सव आत्मनिर्भरता का प्रतीक' थीम ने जीता दिल

इस वर्ष महाराष्ट्र ने 'गणेशोत्सव आत्मनिर्भरता का प्रतीक' थीम पर आधारित झांकी प्रस्तुत की थी। झांकी के माध्यम से राज्य की समृद्ध लोक संस्कृति, गणेशोत्सव की सामाजिक परंपरा और इससे जुड़े रोजगार व आत्मनिर्भरता के संदेश को प्रभावशाली ढंग से दर्शाया गया। कर्तव्य पथ पर विशाल गणेश प्रतिमा और पारंपरिक ढोल-ताशा की गूंज ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया, जिसके चलते निर्णायक मंडल ने इसे सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित किया।

'गर्भाशय कैंसर मुक्त महाराष्ट्र' अभियान का विस्तार

मुख्यमंत्री ने की सहभागिता की अपील

डीबीडी संवाददाता | मुंबई/नाशिक

पुणे और सातारा में सफल शुरुआत के बाद, राज्य सरकार ने अब नासिक जिले में 'सर्वाइकल कैंसर मुक्त महाराष्ट्र' अभियान का विस्तार किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में इस मुहिम को नई गति मिली है, जिसका उद्देश्य महिलाओं और किशोरियों को इस घातक बीमारी से सुरक्षा प्रदान करना है। जल्द ही नासिक में इसकी आधिकारिक शुरुआत होगी, जिससे महाराष्ट्र के कुल 10 प्राथमिकता वाले जिलों में यह जीवनरक्षक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो जाएगी।

हर 8 मिनट में एक मौत: गंभीर होते आंकड़े

भारत में सर्वाइकल कैंसर के आंकड़े डराने वाले हैं; यह महिलाओं में दूसरा सबसे आम कैंसर है। आंकड़ों के अनुसार, देश में हर 8 मिनट में एक महिला की मौत इस बीमारी से होती है। हालांकि, स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि इस कैंसर को समय पर एचपीवी (HPV) टीकाकरण और नियमित जांच के माध्यम से पूरी तरह से रोका जा सकता है।

किशोरियों के लिए सुरक्षा कवच और एचपीवी टीका

इस अभियान का मुख्य केंद्र 9 से 14 वर्ष की आयु की किशोरियां हैं। इस आयु वर्ग की बालिकाओं को एचपीवी टीका लगाकर उनके भविष्य को कैंसर मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि बेटियों का स्वास्थ्य और संरक्षण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने इस सामाजिक दायित्व को निभाने के लिए कॉर्पोरेट क्षेत्र से भी सीएसआर (CSR) फंड के माध्यम से आर्थिक सहयोग देने की अपील की है।

सार्वजनिक-निजी भागीदारी और क्रियान्वयन

इस मिशन की सफलता के लिए 'जीविका फाउंडेशन' राज्य के प्रमुख क्रियान्वयन भागीदार के रूप में कार्य कर रहा है। फाउंडेशन के निदेशक जिग्नेश पटेल के अनुसार, उनकी टीम जमीनी स्तर पर जन-जागरूकता फैलाने और समुदायों के बीच टीके के प्रति विश्वास पैदा करने के लिए सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है।

मराठी भाषा पखवाड़े के मौके पर कवि सम्मेलन का आयोजन

ठाणे मनपा कलाकारों को संभालकर रखता है: अतिरिक्त आयुक्त

डीबीडी संवाददाता | ठाणे

ठाणे महानगरपालिका के अतिरिक्त आयुक्त संदीप मालवी ने मराठी भाषा पखवाड़े के अवसर पर आयोजित कवि सम्मेलन के दौरान मनपा कर्मचारियों की बहुमुखी प्रतिभा की सराहना की। उन्होंने गर्व से कहा कि ठाणे मनपा न केवल प्रशासन बल्कि कला और कलाकारों को सहेजने वाली संस्था के रूप में भी जानी जाती है। 27 जनवरी को स्वर्गीय नरेंद्र बल्लाल हॉल में आयोजित इस गरिमामयी कार्यक्रम में उपायुक्त उमेश बिरारी सहित विभिन्न विभागों के कर्मचारी बड़ी संख्या में मौजूद थे। मालवी ने इस बात पर जोर दिया कि मनपा के भीतर कई बेहतरीन लेखक, गायक और कवि छिपे हैं, जिन्हें मंच प्रदान करना गौरव की बात है।

भावपूर्ण कविताएं और विविध काव्य विधाओं का संगम

इस काव्य गोष्ठी में आमंत्रित कवियों ने अपनी रचनाओं से मानवीय संवेदनाओं के विभिन्न पहलुओं को उजागर किया। रन्यूज़लेस पोएट्री के चामुला, सुनील तांबे, यामिनी दलवी, सुरेश ठामके, पंकज दलवी और प्रशांत डिंगणकर जैसे मंझे हुए रचनाकारों ने गजल, हाइकु, मुक्त छंद और व्यंग्य के माध्यम से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। जहाँ पंकज दलवी की हास्य कविताओं ने हॉल को तालियों से भर दिया, वहीं प्रशांत डिंगांकर के व्यंग्य और यामिनी दलवी की गजलों ने जीवन के गहरे सत्यों को छू लिया। कार्यक्रम का समापन महान कवि नारायण सुर्वे की जन्म शताब्दी और डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ हुआ।

एक दिवसीय बॉक्सिंग टूर्नामेंट का आयोजन

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

सासमीरा कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड साइंस, वरली में 28 जनवरी 2026 को राजन जोथाड़ी सर के मार्गदर्शन में एक दिवसीय बॉक्सिंग टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य छात्रों के बीच बॉक्सिंग जैसे खेल को प्रोत्साहित करना और पढ़ाई के साथ खेलों के महत्व को रेखांकित करना था। विभिन्न कॉलेजों के विद्यार्थियों ने अलग-अलग वजन वर्गों में भाग लिया। सभी मुकाबले मानक नियमों के तहत आयोजित किए गए, जिनकी निगरानी योग्य रेफरी ने की, साथ ही चिकित्सा और सुरक्षा व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित रहीं।

छात्रों के सर्वांगीण विकास पर जोर

टूर्नामेंट का उद्घाटन सासमीरा की वाइस प्रेसिडेंट श्रीमती स्मिता येवले, डायरेक्टर जनरल डॉ. अशोक तिवारी और प्रिंसिपल डॉ. आशिष चुटके ने किया। उन्होंने विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ-साथ खेलों में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया और कहा कि इससे छात्रों का सर्वांगीण विकास संभव है। प्रतियोगिता के दौरान रोमांचक और कड़े मुकाबले देखने को मिले। समापन समारोह में विजेताओं और उपविजेताओं को पदक, प्रमाण पत्र और विशेष ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। यह आयोजन छात्रों के लिए प्रेरणादायक और यादगार अनुभव साबित हुआ।

सेंट्रल रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों की अवधि बढ़ाई

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए सेंट्रल रेलवे ने साईंनगर शिरडी, खड़की, दौंड और सोलापुर के लिए चलाई जा रही स्पेशल ट्रेनों की अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया है। रेलवे प्रशासन के अनुसार ये सभी ट्रेनें मौजूदा रूट, समय-सारिणी, कोच संरचना और निर्धारित स्टॉपेज के साथ ही संचालित होती रहेंगी। इस कदम का उद्देश्य यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा देना और भीड़ का दबाव कम करना है।

इन रूट्स पर मिलेगा विस्तार का लाभ

बीकानेर–साईंनगर शिरडी साप्ताहिक स्पेशल (ट्रेन संख्या 04715/04716) को फरवरी के अंत तक बढ़ाया गया है, जिसमें चार-चार अतिरिक्त ट्रिप शामिल हैं। इसी तरह हिसार–खड़की साप्ताहिक स्पेशल (04725/04726), अजमेर–दौंड साप्ताहिक स्पेशल (09625/09626) और अजमेर–सोलापुर साप्ताहिक स्पेशल (09627/09628) की सेवाओं को भी फरवरी 2026 तक विस्तार दिया गया है।

'मच्छर ला टक्कर' अभियान की शुरुआत

डीबीडी संवाददाता | ठाणे

भारत के 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर ठाणे स्वास्थ्य विभाग ने कीट-जनित बीमारियों के विरुद्ध एक विशेष जन-जागरूकता अभियान 'मच्छर ला टक्कर' की शुरुआत की है। यह अभियान स्वास्थ्य विभाग और 'गोदरेज एम्बेड-FHI' के संयुक्त तत्वावधान में चलाया जा रहा है। इस महत्वपूर्ण पहल का उद्घाटन पुलिस ग्राउंड में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की गरिमामयी उपस्थिति में किया गया। इस अवसर पर जिले के वरिष्ठ प्रशासनिक और स्वास्थ्य अधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने इस अभियान को प्रभावी ढंग से जमीनी स्तर पर उतारने का संकल्प लिया।

बढ़ती बीमारियों के खिलाफ प्रभावी कदम

ठाणे जिले में मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों की बढ़ती संख्या स्वास्थ्य विभाग के लिए एक गंभीर चुनौती बनी हुई है। आंकड़ों के अनुसार, पिछले वर्ष जिले में मलेरिया के 2,073, डेंगू के 1,093 और चिकनगुनिया के 168 मामले दर्ज किए गए थे। इन बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए बचाव और सार्वजनिक जागरूकता को ही सबसे असरदार हथियार माना जा रहा है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संतोषी शिंदे के नेतृत्व में शुरू हुए इस अभियान का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को मच्छरों के प्रजनन को रोकने और सुरक्षा उपाय अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है।

अचोले पुलिस ने 82 मोबाइल किया बरामद

पालघर। पालघर जिले में अचोले पुलिस स्टेशन ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए गुम हुए 82 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इन फोनों की कुल बाजार कीमत लगभग 12.30 लाख आंकी गई है। पुलिस टीम ने तकनीकी जांच के आधार पर इन फोनों को ट्रैक किया और एक विशेष कार्यक्रम के दौरान उन्हें उनके असली मालिकों को वापस लौटा दिया। इस कार्रवाई से उन नागरिकों के चेहरे पर खुशी लौट आई है जो अपने कीमती फोन मिलने की उम्मीद छोड़ चुके थे। अचोले पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले कई इलाके जैसे रेलवे स्टेशन परिसर, गाला नगर, शिर्डी नगर, अलकापुरी साप्ताहिक बाजार और स्टेशन से सटे बाजार अत्यंत घनी आबादी वाले और भीड़भाड़ वाले क्षेत्र हैं।

12 राशिफल में देखें अपना दिन

मेष प्रयास सफल रहेंगे। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। पराक्रम बढ़ेगा। आय में वृद्धि होगी। पराक्रम बढ़ेगा। किसी बड़े काम को करने में रुझान रहेगा। कारोबार में वृद्धि होगी। नौकरी में प्रशंसा प्राप्त होगी। शेयर मार्केट व म्युचुअल फंड से लाभ होगा। चोट व रोग से बचें।

वृष शुभ समाचार प्राप्त होंगे। घर में मेहमानों का आगमन होगा। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। विवेक से कार्य करें। विरोधी सक्रिय रहेंगे। मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। व्यापार-व्यवसाय लाभदायक रहेगा। नौकरी में चैन रहेगा। आय में वृद्धि होगी।

मिथुन पुराना रोग उभर सकता है। किसी बड़ी समस्या से सामना हो सकता है। लेन-देन में विशेष सावधानी रखें। वाणी में हल्के शब्दों के प्रयोग से बचें। दुःखद समाचार मिल सकता है। किसी व्यक्ति से बेवजह विवाद हो सकता है। व्यर्थ भागदौड़ होगी।

कर्क किसी गलती का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जल्दबाजी व लापरवाही न करें। अज्ञात भय सताएगा। पुराना रोग उभर सकता है। भागदौड़ रहेगी। विद्यार्थी वर्ग सफलता हासिल करेगा। किसी आनंदोत्सव में भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा।

सिंह कुसंगति से हानि होगी। पूजा-पाठ में मन लगेगा। कोर्ट व कचहरी के कार्य अनुकूल रहेंगे। लाभ के अवसर हाथ आएंगे। परिवार के साथ समय अच्छा व्यतीत होगा। आर्थिक उन्नति के प्रयास सफल रहेंगे। कारोबार अच्छा चलेगा।

कन्या नई योजना बनेगी। कार्यप्रणाली में सुधार होगा। कारोबार में वृद्धि होगी। जोखिम उठाने का साहस कर पाएंगे। नए व्यापारिक अनुबंध होंगे। धनार्जन होगा। लंबे समय से रुके कार्यों में गति आएगी। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। जोखिम व जमानत के कार्य टालें।

तुला पुराने शत्रु परेशान कर सकते हैं। थकान व कमजोरी रह सकती है। जीवनसाथी के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी। डूबी हुई रकम प्राप्त हो सकती है। लाभ के अवसर हाथ आएंगे। भाग्य का साथ रहेगा। व्यापार में वृद्धि के योग हैं।

वृश्चिक अप्रत्याशित खर्च सामने आएंगे। कर्ज लेना पड़ सकता है। वाणी पर नियंत्रण रखें। दूसरों से अपेक्षा पूर्ण नहीं होने से खिन्नता रहेगी। कार्य में विलंब होगा। स्वास्थ्य का पाया कमजोर रहेगा। पारिवारिक चिंता बनी रहेगी। कीमती वस्तुएं संभालकर रखें।

धनु धनलाभ के अवसर प्राप्त होंगे। शत्रु परास्त होंगे। कोर्ट व कचहरी के कार्य मनोनुकूल रहेंगे। वाहन व मशीनरी आदि के प्रयोग में सावधानी रखें, विशेषकर स्त्रियां रसोई में ध्यान रखें। वाणी में हल्के शब्दों के प्रयोग से बचें। किसी व्यक्ति से बेवजह विवाद हो सकता है।

मकर रोजगार प्राप्ति के प्रयास सफल रहेंगे। व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी। निवेश के सुखद परिणाम आएंगे। अप्रत्याशित लाभ हो सकता है। किसी बड़ी बाधा के दूर होने से प्रसन्नता रहेगी। भाग्य का साथ मिलेगा। पुराना रोग उभर सकता है।

कुंभ जीवनसाथी से सहयोग प्राप्त होगा। सुख के साधन जुटेंगे। कारोबार में वृद्धि होगी। निवेशादि शुभ रहेंगे। नौकरी में सहकर्मी साथ देंगे। स्त्री पक्ष से लाभ होगा। अज्ञात भय रहेगा। लाभ के अवसर हाथ आएंगे। पार्टनरों का सहयोग मिलेगा।

मीन लेन-देन में जल्दबाजी न करें। किसी अपरिचित पर अतिविश्वास न करें। आय में वृद्धि होगी। भूमि व भवन संबंधी योजना बनेगी। कोई बड़ा लाभ हो सकता है। रोजगार प्राप्ति के प्रयास सफल रहेंगे। भाग्य बेहद अनुकूल है, लाभ लें। चोट व रोग से बचें। प्रेम-प्रसंग में अनुकूलता रहेगी। घर-बाहर प्रसन्नता रहेगी।

जब कुंडली में बनते हैं समृद्धि और विनाश के संकेत

भारतीय ज्योतिष में धन को केवल मेहनत या संयोग का परिणाम नहीं माना गया है, बल्कि इसे ग्रहों की स्थिति, उनके आपसी संबंध और भावों की शक्ति से गहराई से जोड़ा गया है। जन्मकुंडली में बृहस्पति, चन्द्र, सूर्य, बुध, शनि, राहु और केतु जैसे ग्रह जिस प्रकार से विभिन्न भावों में स्थित होते हैं, उसी के अनुसार व्यक्ति के जीवन में धन का आगमन, संरक्षण या नाश होता है। कई बार व्यक्ति अत्यधिक परिश्रम करता है, फिर भी धन हाथ में टिकता नहीं, जबकि कोई दूसरा बिना अधिक प्रयास के भी संपन्न दिखाई देता है। इसके पीछे ग्रहयोगों का सूक्ष्म खेल काम करता है, जिसे समझना साधारण दृष्टि से आसान नहीं, लेकिन शास्त्रों ने इसके संकेत विस्तार से दिए हैं।

जब चन्द्रमा तृतीय भाव में स्थित होता है और उसके शत्रु ग्रह अष्टम भाव में बैठे हों, तो ऐसा व्यक्ति मेहनत तो बहुत

प्रियंका जैन
9769994439

करता है, लेकिन अचानक आने वाली परिस्थितियां, गलत निर्णय या भरोसेमंद दिखने वाले लोग ही धनहानि का कारण बन जाते हैं। ऐसे जातक के लिए शास्त्रों में बताया गया है कि सेवा और विनम्रता का भाव अपनाने से इस दोष का प्रभाव कम होता है। घर आए अतिथि को दूध या जल से सेवा देना केवल एक कर्मकांड नहीं, बल्कि मन और वातावरण को संतुलित करने का उपाय है, जिससे धन का प्रवाह स्थिर होता है। बृहस्पति को धन, ज्ञान और विस्तार का कारक माना गया है। जब बृहस्पति लग्न में स्थित हो और उसके शत्रु ग्रह राहु, शुक्र और बुध 1, 2, 5, 9, 11 और 12 भावों में न हों, साथ ही सप्तम भाव भी शुभ हो, तो ऐसे जातक को बुजुर्गों, वरिष्ठों या पूर्वजों से धन की प्राप्ति होती है। यह धन केवल संपत्ति के रूप में नहीं, बल्कि अनुभव, संरक्षण और अवसर के रूप में भी मिल सकता है, जो आगे चलकर समृद्धि का आधार बनता है।

इसके विपरीत, जब बृहस्पति षष्ठ भाव में और बुध द्वादश भाव में स्थित हों, तो विशेषकर 16 या 19 वर्ष की आयु में पिता के धन को हानि पहुंचने के योग बनते हैं। यह स्थिति पारिवारिक असंतुलन, गलत निवेश या अचानक खर्च के रूप में सामने आ सकती है। यह योग बताता है कि उस समय सावधानी और संयम न बरता जाए, तो पूरे परिवार को उसका असर झेलना पड़ सकता है।

कई बार कुंडली में शक्तिशाली योग भी विरोधी ग्रहों के कारण निष्फल हो जाते हैं। जैसे, यदि बृहस्पति और मंगल की युति लग्न में हो, तो जातक में नेतृत्व, साहस और धन कमाने की अद्भुत क्षमता होती है। लेकिन यदि इसी कुंडली में बुध सप्तम भाव में आकर अशुभ प्रभाव देने लगे, तो वही बुद्धि गलत निर्णयों की वजह बन जाती है और कमाया हुआ धन भी नष्ट होने लगता है। यह योग बताता है कि केवल क्षमता होना काफी नहीं, सही दिशा और संतुलन भी उतना ही जरूरी है। कुछ विशेष योग ऐसे भी होते हैं जो व्यक्ति को स्थायी धनवान बनाते हैं। बृहस्पति द्वितीय भाव में, बुध अष्टम भाव में और शनि दशम भाव में स्थित हों, तो जातक मेहनत, अनुशासन और धैर्य के बल पर धन अर्जित करता है। ऐसे लोग धीरे-धीरे लेकिन स्थिर रूप से आगे बढ़ते हैं और उनके पास धन टिकता भी है।

न्यूज ब्रीफ

योगी कैबिनेट ने अजित पवार के निधन पर जताया शोक

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के आकस्मिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए शोक प्रस्ताव पारित किया गया। मंत्रि परिषद ने 28 जनवरी को महाराष्ट्र के बारामती में हुई विमान दुर्घटना में अजित पवार व अन्य लोगों के निधन को अत्यंत दुःखद बताया। कैबिनेट ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए दिवंगत पुण्यात्माओं की शांति की कामना की। कैबिनेट ने कहा कि अजित पवार का असामयिक निधन अपूरणीय क्षति है। अपने दीर्घ सार्वजनिक जीवन में उन्होंने महाराष्ट्र की जनता से गहरा जुड़ाव रखते हुए समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए कार्य किया। गरीबों एवं वंचितों को सशक्त बनाने तथा महाराष्ट्र के विकास के लिए उनकी प्रतिबद्धता सदैव स्मरणीय रहेगी।

बारामती विमान हादसे की निष्पक्ष जांच जरूरी : अविमुक्तेश्वरानंद

वाराणसी। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार से जुड़े विमान हादसे की जांच की आवश्यकता पर जोर दिया है। प्रयागराज से वाराणसी पहुंचने के बाद उन्होंने कहा कि इस घटना को लेकर यदि किसी के मन में संदेह है तो उसका समाधान पारदर्शी जांच से ही संभव है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि विपक्ष की ओर से साजिश की आशंका जताई जा रही है, ऐसे में मामले की विधिवत जांच कर सच्चाई सामने लानी चाहिए। शंकराचार्य ने स्पष्ट किया कि जांच के बाद ही यह तय हो सकेगा कि हादसा मात्र दुर्घटना था या इसके पीछे कोई अन्य कारण।

मुंबई अग्निकांड ने छीनी मीरजापुर के दो मजदूरों की जिंदगी

मीरजापुर। मुंबई की एक टायर गलाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग में मीरजापुर के दो श्रमिकों की मौत हो गई। हलिया थाना क्षेत्र के केवलझर बैधा गांव निवासी भागवत विश्वकर्मा (32) और रघु कोल (35) रोजगार की तलाश में करीब पखवाड़े भर पहले मुंबई गए थे। मंगलवार को फैक्ट्री में अचानक आग भड़क उठी, जिसकी चपेट में आकर दोनों मजदूरों की मौके पर ही जलकर मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद गुरुवार को जब उनके शव एंबुलेंस से गांव पहुंचे, तो परिजनों में कोहराम मच गया। असमय हुई इस घटना से गांव में शोक का माहौल है और दोनों परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।

UGC कानून से सामाजिक तानेबाने को खतरा: बृजभूषण शरण सिंह

गोंडा। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से जुड़े प्रस्तावित कानून को लेकर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि यह कानून शिक्षा के क्षेत्र में भ्रम पैदा करने के साथ-साथ समाज में अनावश्यक विभाजन और टकराव की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। देश के विभिन्न हिस्सों में हो रहा विरोध इस बात का संकेत है कि आम जनमानस इसे स्वीकार नहीं कर रहा। पूर्व सांसद ने कहा कि ग्रामीण भारत में सवर्ण, दलित और पिछड़े वर्गों के बच्चे वर्षों से बिना किसी भेदभाव के एक साथ खेलते-पढ़ते और आगे बढ़ते रहे हैं।

15 लाख शिक्षक-कर्मचारियों को कैशलेस इलाज

एजेंसी । लखनऊ

योगी कैबिनेट में लिया गया बड़ा सामाजिक फैसला, 30 प्रस्तावों को मंजूरी

उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लाखों लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा की मजबूत ढाल प्रदान की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ऐसा निर्णय लिया गया है, जिससे प्रदेश के शिक्षक, शिक्षणेत्तर कर्मचारी और उनके आश्रित अब सरकारी ही नहीं, बल्कि निजी अस्पतालों में भी कैशलेस इलाज की सुविधा प्राप्त कर सकेंगे। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने पत्रकार वार्ता में बताया कि कैबिनेट बैठक में कुल 32 प्रस्ताव रखे गए थे, जिनमें से 30 को स्वीकृति प्रदान की गई। शिक्षकों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा से जुड़ा निर्णय इनमें प्रमुख रहा।

माध्यमिक शिक्षा के कर्मी होंगे लाभांवित

फैसले के तहत माध्यमिक शिक्षा विभाग से जुड़े निम्न वर्गों को अंत:रोगी (IPD) इलाज की कैशलेस सुविधा मिलेगी। इसके तहत अनुदानित विद्यालयों के शिक्षक (व्यावसायिक शिक्षा विषय विशेषज्ञ एवं मानदेय शिक्षक सहित), संस्कृत शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त अनुदानित विद्यालयों के शिक्षक, स्ववित्तपोषित मान्यता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षक और राजकीय व सहायता प्राप्त विद्यालयों में मानदेय पर कार्यरत व्यावसायिक शिक्षा विशेषज्ञ भी योजना के दायरे में आएंगे। इन सभी के आश्रित परिवारजन भी इस सुविधा के दायरे में होंगे। माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने बताया कि इस श्रेणी में 2.97 लाख से अधिक लोग लाभान्वित होंगे, जिन पर लगभग 89.25 करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित है। इस योजना का दायरा केवल माध्यमिक शिक्षा तक सीमित नहीं है। बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े शिक्षक, शिक्षामित्र, विशेष शिक्षक, अनुदेशक, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की वार्डेन, पूर्णकालिक/अंशकालिक शिक्षक, प्रधानमंत्री पोषण योजना के रसोइए और और उनके आश्रित भी इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के अनुसार, इस श्रेणी में 11.95 लाख से अधिक शिक्षक व कर्मी शामिल होंगे। प्रति कर्मी करीब 3000 रुपये वार्षिक प्रीमियम के आधार पर सरकार पर 358.61 करोड़ रुपये का वार्षिक व्यय आएगा।

448 करोड़ रुपये का समग्र व्यय अनुमानित

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते वर्ष शिक्षक दिवस के अवसर पर इस योजना की घोषणा की थी। अब कैबिनेट की स्वीकृति के साथ यह घोषणा मूर्त रूप ले चुकी है। इस निर्णय से बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग से जुड़े करीब 15 लाख शिक्षक व कर्मचारी लाभान्वित होंगे। योजना पर कुल मिलाकर लगभग 448 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

निजी अस्पतालों में भी इलाज की सुविधा

योगी कैबिनेट में लिए गए फैसले के मुताबिक इन कर्मियों को कैशलेस इलाज की सुविधा सरकारी अस्पतालों के साथ-साथ सूचीज (SACHIS) से संबद्ध निजी अस्पतालों में भी उपलब्ध होगी। इलाज की दरें प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप होंगी। योजना का लाभ सत्यापन के बाद दिया जाएगा। स्ववित्तपोषित मान्यता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों को योजना का लाभ वेरिफिकेशन के बाद मिलेगा।

पूर्वी पाकिस्तान से आए 99 परिवारों को मिलेगा स्थाई आशियाना

इन दो गांवों में होगा पुनर्वासन

- ग्राम भैंसाया में 11.1375 हेक्टेयर (27.5097 एकड़) भूमि पर 50 परिवार
- ग्राम ताजपुर तरसौली में 10.530 हेक्टेयर (26.009 एकड़) भूमि पर 49 परिवार
- प्रत्येक परिवार को 0.50 एकड़ भूमि आवंटित की जाएगी।

एजेंसी । लखनऊ

उत्तर प्रदेश सरकार ने दशकों से विस्थापन की पीड़ा झेल रहे हिंदू बंगाली परिवारों के जीवन में स्थायित्व लाने की दिशा में अहम कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) से आए 99 विस्थापित परिवारों के स्थायी पुनर्वासन को स्वीकृति प्रदान की गई।

मेरठ से कानपुर देहात तक होगा पुनर्वास

कैबिनेट के फैसले के तहत मेरठ जनपद की तहसील मवाना स्थित ग्राम नंगला गोसाई में झील की भूमि पर लंबे समय से रह रहे इन परिवारों को अब कानपुर देहात जनपद में बसाया जाएगा। सरकार ने पुनर्वासन के लिए रसूलाबाद तहसील के दो गांवों में भूमि चिन्हित की है।

30 वर्ष का पट्टा, 90 वर्ष तक नवीनीकरण

आवंटित भूमि प्रीमियम अथवा लीज रेंट पर 30 वर्ष के पट्टे पर दी जाएगी। सरकार ने इसमें दीर्घकालिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 30-30 वर्ष के लिए नवीनीकरण की सुविधा भी दी है, जिससे पट्टे की अधिकतम अवधि 90 वर्ष तक हो सकेगी। इस निर्णय से वर्षों से अस्थायी और असुरक्षित परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहे परिवारों को स्थायी ठिकाना मिलेगा। सरकार का मानना है कि यह कदम न केवल पुनर्वासन बल्कि सामाजिक सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन की दिशा में भी महत्वपूर्ण साबित होगा।

आतंकी फैजान से पूछताछ करेगी UP ATS

गुजरात के नवसारी से हुई है गिरफ्तारी, रामपुर निवासी आतंकी से पूछताछ करने अहमदाबाद पहुंची यूपी की टीम

एजेंसी । लखनऊ

गुजरात के नवसारी से संदिग्ध आतंकी फैजान की गिरफ्तारी के बाद उत्तर प्रदेश एटीएस भी अलर्ट मोड में आ गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए यूपी एटीएस की एक विशेष टीम अहमदाबाद के लिए रवाना हुई है, जहां आरोपी से गहन पूछताछ की जाएगी। जांच एजेंसियों को आशंका है कि फैजान के तार उत्तर प्रदेश से जुड़े नेटवर्क से भी जुड़े हो सकते हैं। गुजरात एटीएस ने फैजान को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया था। उसके पास से एक पिस्टल और छह कारतूस बरामद हुए हैं। आरोपी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले का निवासी बताया जा रहा है और नवसारी में दर्जी का काम कर रहा था। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि वह आतंक फैलाने की मंशा से हथियार जुटा रहा था।

टारगेटेड दहशत फैलाने का था इरादा

जांच एजेंसियों के अनुसार पूछताछ में फैजान ने स्वीकार किया है कि वह पिछले छह से सात महीनों से अबू बकर नामक व्यक्ति के संपर्क में था और करीब तीन महीने पहले एक संदिग्ध ग्रुप से जुड़ा था। उसने यह भी बताया कि हथियार उसने करीब छह महीने पहले उत्तर प्रदेश में किसी व्यक्ति से हासिल किए थे। उसका इरादा टारगेटेड हत्याओं के जरिए दहशत फैलाने का था।

मोबाइल से मिले महत्वपूर्ण दस्तावेज

जांच के दौरान जब उसका मोबाइल फोन खंगाला गया तो उसमें कई आपत्तिजनक सामग्री मिली। चैट और वीडियो के जरिए जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े प्रचार वीडियो, भड़काऊ भाषण और कुख्यात आतंकियों के वीडियो सामने आए हैं। इसके अलावा मोबाइल से देश विरोधी तस्वीरें और कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बरामद होने की बात कही जा रही है।

रामपुर में ठिकानों पर की जा रही जांच

पूछताछ के दौरान आतंकी साजिश से जुड़े कई अहम सुराग मिले हैं, जिनके आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। यूपी एटीएस रामपुर में उसके संभावित सहयोगियों, संपर्कों और ठिकानों की भी पड़ताल कर रही है। एजेंसियों का कहना है कि पूरे नेटवर्क की परतें खोलने के लिए पूछताछ का दायरा और बढ़ाया जाएगा।

दीवार फांद भागे दो बंदी जेल अधीक्षक सस्पेंड

जेल की सुरक्षा में लगाई सेंध, फिर लांघी दीवार

एक हत्या तो दूसरा दुष्कर्म के मामले में था बंद

एजेंसी । अयोध्या

जनपद की जिला कारागार व्यवस्था उस समय कटघरे में आ गई, जब गुरुवार को दो विचाराधीन बंदी जेल परिसर से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही जेल प्रशासन में अफरा-तफरी मच गई और फरार बंदियों की धरपकड़ के लिए पुलिस व प्रशासनिक अमला सक्रिय हो गया। सूचना मिलते ही जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. गौरव ग्रोवर जिला जेल पहुंचे और मौके पर सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों बंदियों को तन्हाई बैरक में रखा गया था, जहां से उन्होंने बैरक की संरचना को क्षतिग्रस्त कर बाहर निकलने का रास्ता बनाया और इसके बाद जेल की बाउंड्री वॉल लांघकर फरार हो गए।

एक अमेठी तो दूसरा सुल्तानपुर का

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. गौरव ग्रोवर ने बताया कि फरार बंदियों की पहचान गोलू अग्रहरि उर्फ सूरज अग्रहरी, निवासी अमेठी और शेर अली, निवासी सुल्तानपुर के रूप में हुई है। इनमें से एक बंदी हत्या के प्रयास के मामले में, जबकि दूसरा दुष्कर्म के आरोप में जिला जेल में निरुद्ध था। दोनों बंदियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें गठित की गई हैं और संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। साथ ही जेल परिसर की सुरक्षा व्यवस्था, निगरानी तंत्र और ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों की भूमिका की भी गहन समीक्षा की जा रही है। इस मामले में डीजी जेल पीसी मीणा ने वरिष्ठ जेल अधीक्षक उदय प्रताप मिश्र, जेलर जेके यादव, डिप्टी जेलर मयंक त्रिपाठी समेत एक हेड जेल वॉर्डन और तीन वार्डन को सस्पेंड कर दिया है।

माघ के अंतिम दिनों में पारा 11 डिग्री सेल्सियस

जौनपुर। जिले में मौसम ने एक बार फिर रुख बदल लिया है। सुबह से छाए बादलों और ठंडी हवाओं के चलते गलन में तीव्रता आ गई है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। ठंड बढ़ने के कारण लोगों को दिन की शुरुआत ही कंपकंपी के साथ करनी पड़ी और कई दिनों बाद सार्वजनिक स्थानों पर लोग अलाव तापते नजर आए। बीते बुधवार को धूप निकलने से राहत जरूर मिली थी, लेकिन शाम ढलते ही सर्दी फिर हावी हो गई। गुरुवार को अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान गिरकर 11 डिग्री तक पहुंच गया। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार इस दौरान आर्द्रता 89 प्रतिशत रही, वायु गुणवत्ता सूचकांक 124 दर्ज किया गया और हवा की रफ्तार लगभग 10 किलोमीटर प्रति घंटा रही। इसके मुकाबले बुधवार को न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहा था, जबकि आर्द्रता 79 प्रतिशत और वायु गुणवत्ता सूचकांक 131 मापा गया था। मौसम में आए इस अचानक बदलाव का सीधा असर लोगों के स्वास्थ्य पर भी देखने को मिल रहा है।

व्यापार जगत

सर्वे ने बदला बाजार का मूड, दमदार वापसी

तीसरे दिन भी तेजी बरकरार, सेंसेक्स-निफ्टी ने निचले स्तर से लगाई जोरदार छलांग

एजेंसी । नई दिल्ली

संसद में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण के सकारात्मक संकेतों ने घरेलू शेयर बाजार को नई ऊर्जा दी, जिससे शुरुआती दबाव के बावजूद बाजार लगातार तीसरे कारोबारी दिन मजबूती के साथ बंद होने में सफल रहा। दिन की शुरुआत में वैश्विक बाजारों से मिले नकारात्मक संकेतों के कारण भारी बिकवाली देखने को मिली, लेकिन आर्थिक सर्वे सामने आते ही निवेशकों का भरोसा लौटा और बाजार ने तेज रिकवरी दर्ज की। कारोबार के दौरान सेंसेक्स अपने निचले स्तर से करीब 982 अंकों की उछाल के साथ संभला, जबकि निफ्टी ने लगभग 298 अंकों की जोरदार वापसी की। दिन के अंत में सेंसेक्स 0.27 प्रतिशत और निफ्टी 0.30 प्रतिशत की बढ़त के साथ बंद हुए। सेक्टोरल प्रदर्शन की बात करें तो फार्मा, आईटी और एफएमसीजी शेयरों में दिनभर दबाव बना रहा। ऑटो, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और टेक्नोलॉजी इंडेक्स भी कमजोरी के साथ बंद हुए। इसके विपरीत मेटल, ऑयल एंड गैस और पावर सेक्टर में जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली। बैंकिंग, एनर्जी, कैपिटल गुड्स और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों ने भी बाजार को सहारा दिया। हालांकि चुनिंदा शेयरों को छोड़कर व्यापक बाजार में बिकवाली का माहौल बना रहा।

बढ़त के साथ बंद हुए 1702 शेयर

कारोबार के आंकड़ों पर नजर डालें तो बीएसई में 4,389 शेयरों में ट्रेडिंग हुई, जिनमें से 1,702 शेयर बढ़त के साथ बंद हुए, जबकि 2,534 शेयरों में गिरावट रही और 153 शेयर स्थिर रहे। एनएसई में 2,922 शेयरों में कारोबार हुआ, जिनमें 1,205 शेयर हरे निशान में और 1,717 शेयर लाल निशान में बंद हुए। सेंसेक्स के 30 में से 13 शेयरों ने बढ़त दर्ज की, जबकि निफ्टी-50 के 22 शेयर तेजी के साथ बंद हुए। सेंसेक्स ने दिन की शुरुआत 82,368.96 अंकों से की, लेकिन कुछ ही देर में यह 636 अंकों से अधिक टूटकर 81,707.94 तक फिसल गया। इसके बाद आर्थिक सर्वे के पेश होते ही घरेलू और विदेशी निवेशकों की चौतरफा खरीदारी शुरू हुई, जिससे सूचकांक तेज गति से चढ़ा और दिन में एक समय 82,689.96 के स्तर तक पहुंच गया।

उतार-चढ़ाव के बीच निफ्टी की छलांग

निफ्टी ने भी इसी तरह का उतार-चढ़ाव दिखाया। शुरुआती कारोबार में गिरकर 25,159.80 तक पहुंचने के बाद इसमें मजबूत रिकवरी देखने को मिली और यह 25,458.15 तक गया। दिन के अंत में यह 76.15 अंकों की बढ़त के साथ 25,418.90 अंक पर बंद हुआ।

एक दिन में 23 हजार करोड़ का फायदा

बाजार में आई इस तेजी से निवेशकों की संपत्ति में उल्लेखनीय इजाफा हुआ। बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़कर 459.76 लाख करोड़ रुपये (अनंतिम) पहुंच गया, जो पिछले कारोबारी दिन 459.53 लाख करोड़ रुपये था। इस तरह एक ही दिन में निवेशकों को करीब 23 हजार करोड़ रुपये का लाभ हुआ।

वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत की रफ्तार कायम: खंडेलवाल

नई दिल्ली। भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 ने वैश्विक मंदी के दौर में भारत की स्थिरता और विकास क्षमता को रेखांकित किया है। यह बातें भारतीय जनता पार्टी के सांसद और कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने कही। लोकसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए खंडेलवाल ने कहा कि वर्ष 2026-27 के लिए 6.8 से 7.2 प्रतिशत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर भारत की मजबूत आर्थिक नींव और नीतिगत स्पष्टता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि जब दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं महंगाई, भू-राजनीतिक तनाव और आर्थिक सुस्ती से जूझ रही हैं, ऐसे समय में भारत का यह प्रदर्शन उल्लेखनीय है। खंडेलवाल ने कहा कि प्रतिकूल वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद विकास की निरंतरता इस बात का प्रमाण है कि देश में अपनाई गई आर्थिक नीतियां सही दिशा में हैं। आर्थिक सर्वेक्षण यह भी स्पष्ट करता है कि भारत वैश्विक स्तर पर अब भी सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है।

निवेशकों और आम नागरिकों के बीच मजबूत हुआ भरोसा

उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व को देते हुए कहा कि संरचनात्मक सुधार, बुनियादी ढांचे में बड़े निवेश, विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा, एमएसएमई सेक्टर को सशक्त करने और कारोबार को आसान बनाने की पहलों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को नई मजबूती दी है। कैट महामंत्री ने कहा कि आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 आगामी केंद्रीय बजट 2026-27 के लिए ठोस दिशा प्रदान करता है। इससे व्यापार जगत, एमएसएमई, निवेशकों और आम नागरिकों के बीच भरोसा और मजबूत हुआ है कि भारत वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर तेजी से अग्रसर है।

बाणगंगा पेपर इंडस्ट्रीज में स्वामीनाथन मुरलीधरन बने अतिरिक्त कार्यकारी निदेशक

एजेंसी । मुंबई

एस्गार्ड एल्कोबेव लिमिटेड (पूर्व में बाणगंगा पेपर इंडस्ट्रीज लिमिटेड) ने श्री स्वामिनाथन मुरलीधरन को 28 जनवरी 2026 से अतिरिक्त निदेशक (कार्यकारी) नियुक्त किया है। वे कंपनी के बोर्ड और कार्यकारी प्रबंधन टीम का हिस्सा बनकर उत्पादन और तकनीकी कार्यों का नेतृत्व करेंगे। कंपनी के एल्कोबेव कारोबार के विस्तार के बीच उनकी भूमिका उत्पादन दक्षता, गुणवत्ता सुधार, लागत नियंत्रण और रणनीतिक विकास पर केंद्रित रहेगी। श्री मुरलीधरन को अल्कोहलिक बेवरेज और विनिर्माण क्षेत्रों में 46 वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने भारत और विदेशों में ब्रुअरी, डिस्टिलरी और बॉटलिंग संचालन से जुड़ी कई वरिष्ठ भूमिकाएं निभाई हैं। बीपीआईएल से पहले वे राजस्थान में 300 केएलपीडी ग्रीनफील्ड एथेनॉल प्लांट परियोजना से जुड़े थे। कंपनी प्रबंधन ने कहा कि उनका अनुभव संगठन की दीर्घकालिक विकास रणनीति को मजबूती देगा। मुरलीधरन ने भी कंपनी की बाजार स्थिति और परिचालन क्षमताओं को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई। कंपनी ने हाल ही में अपना नाम बदलकर एस्गार्ड एल्कोबेव लिमिटेड किया है और सीएमजे ब्रेवरीज़ प्राइवेट लिमिटेड में 78.90% हिस्सेदारी अधिग्रहित कर एल्कोबेव क्षेत्र में रणनीतिक प्रवेश किया है। भारतीय बीयर बाजार में तेज वृद्धि को देखते हुए कंपनी भविष्य में विस्तार की मजबूत संभावनाएं देख रही है।

केंद्र सरकार की डिजाइन संरक्षण कानून में बड़े बदलाव की तैयारी

DPIIT ने सार्वजनिक किए संशोधित प्रस्ताव

एजेंसी । नई दिल्ली

भारत के डिजाइन संरक्षण कानून को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप ढालने की दिशा में केंद्र सरकार ने अहम कदम बढ़ाया है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) ने डिजाइन एक्ट, 2000 में व्यापक संशोधन के लिए एक अवधारणा पत्र जारी किया है, जिसका उद्देश्य देश के डिजाइन संरक्षण ढांचे को आधुनिक और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुकूल बनाना है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार, प्रस्तावित संशोधनों के जरिए भारत को रियाद डिजाइन कानून संधि (डिजाइन लॉ ट्रीटी) और औद्योगिक डिजाइनों के अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण से जुड़े हेग समझौते के साथ तालमेल में लाने की योजना है। सरकार का मानना है कि इससे भारत का डिजाइन इकोसिस्टम मजबूत होगा और 'डिजाइन इन इंडिया, डिजाइन फॉर द वर्ल्ड' की परिकल्पना को नई गति मिलेगी।

डिजिटल डिजाइन को कानूनी सुरक्षा

अवधारणा पत्र में डिजाइन कानून के कई प्रावधानों में बदलाव का सुझाव दिया गया है। इनमें 'डिजाइन' और 'आर्टिकल' की परिभाषा में संशोधन कर वर्चुअल और डिजिटल डिजाइनों को कानूनी सुरक्षा देना, 12 महीने की ग्रेस पीरियड व्यवस्था लागू करना और डिजाइन के प्रकाशन को 30 महीने तक टालने का विकल्प शामिल है। इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय संधियों के अनुरूप समय-सीमा में राहत, वैधानिक क्षतिपूर्ति का प्रावधान, डिजाइन संरक्षण की अवधि में संशोधन और एक ही आवेदन में कई डिजाइनों को दर्ज करने की सुविधा का प्रस्ताव भी रखा गया है।

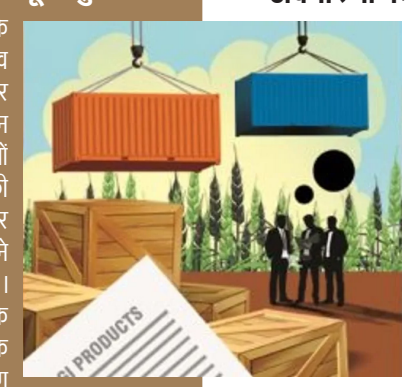

अवधारणा पत्र DPIIT की वेबसाइट पर

प्रस्तावों में आवेदनों के वर्गीकरण को अधिक लचीला बनाने और हेग समझौते व डिजाइन लॉ ट्रीटी के अनुरूप अन्य प्रक्रियात्मक सुधारों को भी शामिल किया गया है, ताकि डिजाइन पंजीकरण की प्रक्रिया सरल, तेज और प्रभावी हो सके। डीपीआईआईटी ने इन प्रस्तावों पर उद्योग जगत, डिजाइन पेशेवरों, कानूनी विशेषज्ञों और अन्य हितधारकों से सुझाव और टिप्पणियां आमंत्रित की हैं। विभाग का कहना है कि प्राप्त फीडबैक के आधार पर आगे की चर्चा और अंतिम संशोधनों को आकार दिया जाएगा। अवधारणा पत्र सार्वजनिक परामर्श के लिए डीपीआईआईटी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है।

गुजरात और मुंबई की निगाह प्लेऑफ पर

महिला प्रीमियर लीग

एजेंसी । वडोदरा

महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) में शुक्रवार को वडोदरा के मैदान पर मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस और गुजरात जायंट्स के बीच एक बेहद अहम मुकाबला खेला जाएगा। प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए दोनों ही टीमों के लिए यह मैच 'करो या मरो' जैसा है। दोनों टीमें जीत दर्ज कर अंतिम चार में अपनी जगह सुरक्षित करने के इरादे से मैदान में उतरेंगी, जिससे दर्शकों को एक कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है।

गुजरात के पास प्लेऑफ पक्का करने का मौका

अंक तालिका पर नजर डालें तो गुजरात जायंट्स फिलहाल 8 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है और उसका नेट रन रेट -0.271 है। यदि गुजरात इस मैच में मुंबई को हरा देती है, तो वह लगातार दूसरी बार प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर लेगी। इतना ही नहीं, अगर वे एक रिकॉर्ड अंतर से जीत दर्ज करते हैं, तो सीधे फाइनल में पहुंचने की भी संभावना बन सकती है। फिलहाल, गुजरात का भाग्य पूरी तरह से उनके अपने हाथों में है।

अगर-मगर के समीकरण

यदि गुजरात हार भी जाती है, तो भी उनकी उम्मीदें पूरी तरह खत्म नहीं होंगी, लेकिन तब उन्हें यूपी वॉरियर्स की जीत पर निर्भर रहना होगा। वहीं, अगर मुंबई यह मैच हार जाती है, तो उन्हें दुआ करनी होगी कि दिल्ली कैपिटल्स अपने आखिरी लीग मैच में यूपी वॉरियर्स से हार जाए, जिसके बाद फैसला नेट रन रेट के आधार पर होगा।

मुंबई का पलड़ा भारी

हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली मुंबई इंडियंस के पास 6 अंक हैं और उनका नेट रन रेट 0.146 है। आंकड़ों की बात करें तो मुंबई का पलड़ा भारी नजर आता है, क्योंकि पिछले लगातार आठ मुकाबलों में गुजरात को मुंबई के हाथों हार का सामना करना पड़ा है। मुंबई अपनी इस बादशाहत को कायम रखना चाहेगी, जबकि गुजरात की टीम हार के इस पुराने सिलसिले को तोड़कर नया इतिहास रचने के लिए प्रतिबद्ध होगी।

फॉर्म में हैं दोनों टीमों के स्टार खिलाड़ी

दोनों ही टीमें अपने पिछले मुकाबलों में जीत दर्ज कर आत्मविश्वास से लबरेज हैं। गुजरात ने सोफी डिवाइन के शानदार प्रदर्शन के दम पर पिछले मैच में दिल्ली कैपिटल्स को 3 रन से हराया था। वहीं, मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) को 15 रन से मात दी थी।

गुकेश ने जीत के साथ वापसी की, एरिगेसी फिर हारे

टाटा स्टील मास्टर्स

विज्क आन जी। टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट में विश्व चैंपियन डी. गुकेश ने दमदार वापसी की है। नीदरलैंड्स के विज्क आन जी में खेले जा रहे इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में गुकेश ने युवा खिलाड़ी यागिज कान एर्दोगमस को काले मोहरों से हराया। इस जीत के साथ उनके संभावित 10 में से पांच अंक हो गए हैं और वह फिर से खिताबी दौड़ में बने हुए हैं।

अरिगेसी की फॉर्म चिंता का विषय

भारत के शीर्ष रैंकिंग खिलाड़ी अर्जुन एरिगेसी को एक बार फिर हार का सामना करना पड़ा। जर्मनी के विन्सेंट कीमर के खिलाफ वह अंतिम क्षणों में मुकाबला संभाल नहीं सके। कुछ दिन पहले तक शानदार फॉर्म में दिख रहे एरिगेसी इस टूर्नामेंट में अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर पाए हैं और दस मैचों में चार अंकों के साथ अंक तालिका के निचले पायदान पर हैं। वहीं, आर. प्रज्ञाननंदा ने अमेरिकी ग्रैंडमास्टर हैंस मोके नीमन के साथ बाजी ड्रॉ खेली।

न्यूज ब्रीफ

फायर ओपन के दूसरे दौर में सेंथिलकुमार और चोटरानी

नई दिल्ली। राष्ट्रीय चैंपियन वेलवन सेंथिलकुमार और वीर चोटरानी ने वाशिंगटन में चल रही स्क्वॉश ऑन फायर ओपन की पीएसए कांस्य स्तर की प्रतियोगिता में शानदार शुरुआत करते हुए अगले दौर में प्रवेश किया। दुनिया के 46वें नंबर के खिलाड़ी सेंथिलकुमार ने इंग्लैंड के टॉम वॉल्श को 12-14, 11-8, 11-8, 11-6 से हराया। दूसरे दौर में उनका सामना मैक्सिको के लियोनेल कार्डेनास से होगा। दुनिया के 49वें नंबर के खिलाड़ी चोटरानी ने हंगरी के बालाज फार्कस को 6-11, 9-11, 11-5, 11-9, 11-3 से पराजित किया। अगले दौर में उन्हें फ्रांस के चौथे वरीय बैपटिस्ट मासोटी की चुनौती से पार पाना होगा। राष्ट्रीय चैंपियन और सातवीं वरीयता प्राप्त अनाहत सिंह को पहले दौर में बाई मिली है।

टी-20 विश्व कप से पहले एसएससी का कायाकल्प

कोलंबो। अगले महीने शुरू होने वाले टी-20 विश्व कप से पहले कोलंबो स्थित सिंहली स्पोर्ट्स क्लब (एसएससी) स्टेडियम का बड़े पैमाने पर नवीनीकरण किया गया है। इस प्रतिष्ठित मैदान में अब फ्लडलाइट्स लगाई गई हैं, जिससे यह श्रीलंका का पांचवां अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बन गया है, जहां दिन-रात्रि मुकाबले खेले जा सकते हैं। सात फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच विश्व कप का पहला मैच इसी मैदान पर खेला जाएगा। फ्लडलाइट्स की सुविधा मिलने के साथ ही एसएससी अब कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम, कैंडी के पल्लेकेले स्टेडियम, दांबुला के रंगिरि दांबुला स्टेडियम और हंबनटोटा के महिंदा राजपक्षे स्टेडियम की सूची में शामिल हो गया है। यह नवीनीकरण टूर्नामेंट के आयोजन और दर्शकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए किया गया है। एसएससी ने 1982 में श्रीलंका में खेले गए पहले वनडे मैच की मेजबानी की थी और यहीं श्रीलंका क्रिकेट (एसएलसी) का मुख्यालय भी स्थित है। श्रीलंका क्रिकेट के कोषाध्यक्ष सुजीवा गोदालियाड्डा के अनुसार, नई प्रकाश व्यवस्था अत्याधुनिक एलईडी तकनीक पर आधारित है, जिसे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट और प्रसारण की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया गया है।

खत्म नहीं हुईं बृजभूषण सिंह की मुश्किलें

पहलवान यौन उत्पीड़न मामले में जारी रहेगा ट्रायल: कोर्ट

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत देने से इनकार कर दिया है। महिला पहलवानों द्वारा दर्ज कराए गए यौन उत्पीड़न के मामले में अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। कोर्ट के इस रुख से साफ है कि सिंह की मुश्किलें अभी कम नहीं हुई हैं और ट्रायल कोर्ट में मुकदमे की प्रक्रिया बदस्तूर जारी रहेगी।

21 अप्रैल को अगली सुनवाई

न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने बृजभूषण सिंह द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर (FIR) और आरोपों को रद्द करने की मांग की थी। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 21 अप्रैल की तारीख तय की है। इसके साथ ही, हाई कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए निचली अदालत से केस से जुड़ा पूरा रिकॉर्ड भी तलब किया है ताकि तथ्यों की गहराई से जांच की जा सके।

रविवार को पूनावाला इंडियन डर्बी आयोजन

बी डी यादव । मुंबई

देश की सबसे प्रतिष्ठित घुड़दौड़ इंडियन डर्बी इस बार बिल्कुल नये अंदाज में रविवार, एक फरवरी 2026 को ऐतिहासिक महालक्ष्मी रेस कोर्स में आयोजित की जाएगी। पहली इंडियन डर्बी आजादी के पहले 1943 में आयोजित की गई थी, उसके बाद हर साल इसकी लोकप्रियता में बढ़ोत्तरी होती गई है। रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब ने पिछले कई वर्षों से अनुबंधित कंपनी हॉर्स पॉवर स्पोर्ट्स लीग कंपनी से विवादों के कारण उसके प्रायोजन के अधिकार को छिन लिया है। तत्पश्चात देश का अग्रणी उद्योग घराना और घुड़दौड़ का शौकीन पूनावाला ग्रुप ने अगले पांच सालों के लिए इस घुड़दौड़ को प्रायोजित करने का अनुबंध किया है। इन पांच वर्षों के लिए डॉ. साइरस एस पूनावाला

और आदर सी पूनावाला रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब को करीब 22 करोड़ रुपये बतौर प्रायोजक के तौर पर देने वाले हैं, जिसके कारण विल्लू सी पूनावाला इंडियन डर्बी की ईनामी राशि में जोरदार बढ़ोत्तरी हुई है। सन 2026 के विल्लू सी पूनावाला इंडियन डर्बी के विजेता को दो करोड़ 40 लाख रुपये की ईनामी राशि प्रदान की जाएगी। मुंबईकरों में इंडियन डर्बी को लेकर एक अलग ही उत्साह रहता है, इस दिन महालक्ष्मी रेसकोर्स पर एक पर्व से वातावरण रहता है, जिसमें घुड़दौड़ शौकीनों के साथ-साथ पहली बार महालक्ष्मी रेसकोर्स पर आने वाले लोग भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इस बार रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब की ओर से जैकपॉट की राशि में एक करोड़ की राशि जोड़ी गई है, जो कि शौकीनों के लिए एक अलग से ही आकर्षण का केन्द्र रहेगी। इसके अलावा पूनावाला ग्रुप द्वारा विल्लू सी पूनावाला इंडियन डर्बी को यादगार बनाने के लिए और कई प्रकार के मनोरंजनपूर्ण कार्यक्रम रखे गये हैं, जिसके कारण मुंबईकरों का महालक्ष्मी रेसकोर्स पर खीचे चले आना स्वाभाविक है। शाम 5.45 बजे आयोजित दौड़ में कुल 11 घोड़े हिस्सा ले रहे हैं। घुड़दौड़ शौकीनों से भरे खचा-खच महालक्ष्मी रेसकोर्स पर विल्लू सी पूनावाला इंडियन डर्बी को जीतने के लिए सभी पेशेवर अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करने को तैयार हैं।

हीली की जगह मोलिनी संभालेंगी ऑस्ट्रेलिया की कमान

एजेंसी । सिडनी।

ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम में बड़ा नेतृत्व परिवर्तन किया गया है। सिडनी में जारी घोषणा के अनुसार, ऑलराउंडर सोफी मोलिनी को भारत के खिलाफ होने वाली टी-20 सीरीज के लिए टीम की कप्तानी सौंपी गई है। घरेलू सीरीज के बाद वह एलिसा हीली की जगह सभी प्रारूपों में ऑस्ट्रेलिया की नियमित कप्तान होंगी। हीली ने भारत के खिलाफ सीरीज के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया है।

वेस्टइंडीज दौरे से पूर्णकालिक कप्तान बनेंगी मोलिनी

मार्च में होने वाले वेस्टइंडीज दौरे से सोफी मोलिनी सभी प्रारूपों में ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी संभालेंगी। टीम प्रबंधन ने ताहलिया मैकग्रा को उपकप्तान के रूप में बनाए रखा है, जबकि एशले गार्डनर को भी उपकप्तान नियुक्त किया गया है। इस बदलाव को ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट के भविष्य की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है।

भारत दौरे में हीली अंतिम बार कप्तान

भारत के खिलाफ सीरीज में एलिसा हीली तीन वनडे और एक टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलियाई टीम की अगुआई करेंगी। भारत का ऑस्ट्रेलिया दौरा 15 फरवरी से सिडनी में शुरू होने वाली तीन मैचों की टी-20 सीरीज से होगा। इसके बाद 24 फरवरी से 1 मार्च के बीच वनडे सीरीज और फिर 6 से 9 मार्च तक एकमात्र टेस्ट मैच खेला जाएगा।

बॉलीवुड

इम्तियाज अली संग दिलजीत दोसांझ की नई फिल्म

रिलीज डेट का ऐलान

इम्तियाज अली के निर्देशन में बनी फिल्म 'अमर सिंह चमकीला' को मिली जबरदस्त सराहना के बाद दर्शक उनकी अगली फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। पिछले साल इम्तियाज ने दिलजीत दोसांझ के साथ अपने नए प्रोजेक्ट की घोषणा की थी और अब इस फिल्म को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। भले ही फिल्म का शीर्षक अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन निर्माताओं ने इसकी रिलीज डेट का ऐलान कर उत्साह बढ़ा दिया है।

यह अनटाइटल्ड फिल्म अप्लॉज एंटरटेनमेंट, विंडो सीट फिल्म्स और इम्तियाज अली मिलकर बना रहे हैं। इसे प्यार, जुदाई और गहरी भावनाओं से जुड़ी कहानी बताया जा रहा है। फिल्म की शूटिंग अगस्त 2025 में शुरू हुई थी। पहले इसे अप्रैल 2026 में रिलीज करने की योजना थी, लेकिन अब इसकी तारीख बदल दी गई है। फिलहाल फिल्म पोस्ट-प्रोडक्शन में है और अब यह 12 जून 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। इस फिल्म में दिलजीत दोसांझ के साथ पहली बार शरवरी की जोड़ी नजर आएगी। इसके अलावा वेदांग रैना और दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह भी अहम भूमिकाओं में दिखाई देंगे। चर्चाओं के मुताबिक कहानी भारत-पाकिस्तान बंटवारे के दौर से जुड़ी हो सकती है, हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है। खास बात यह भी है कि इम्तियाज अली एक बार फिर ए.आर. रहमान और गीतकार इरशाद कामिल के साथ काम कर रहे हैं, यह वही तिकड़ी है जिसने 'रॉकस्टार' और 'तमाशा' जैसे यादगार संगीत से सजी फिल्में दी थीं।

'हेरा फेरी 3' की राह में अड़चन, परेश रावल ने किया बड़ा खुलासा

बॉलीवुड की चर्चित कॉमेडी फ्रैंचाइजी 'हेरा फेरी 3' लंबे समय से अपनी स्टारकास्ट से ज्यादा विवादों को लेकर चर्चा में बनी हुई है। फिल्म को लेकर तरह-तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं, लेकिन अब अभिनेता परेश रावल ने इन अफवाहों पर विराम लगा दिया है। हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने फिल्म की स्थिति और अक्षय कुमार के साथ अपने कथित विवाद पर खुलकर बात की।

'सब कछुआ छाप अगरबत्ती है'

अफवाहें थीं कि अक्षय कुमार ने फिल्म अचानक छोड़ने के चलते परेश रावल पर 25 करोड़ रुपये का मानहानि केस कर दिया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए परेश ने मजाकिया अंदाज़ में कहा, वो सब 'कछुआ छाप अगरबत्ती' है, यानी बेकार की बातें। उन्होंने साफ किया कि फिल्म 100 प्रतिशत बन रही है और उनके व अक्षय के बीच किसी तरह की कानूनी लड़ाई नहीं है।

देरी की असली वजह कुछ और

परेश रावल ने यह भी स्पष्ट किया कि फिल्म के अटकने के पीछे उनकी कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने बताया कि देरी का कारण उनके और अक्षय के बीच कोई झगड़ा नहीं, बल्कि अक्षय कुमार और फिल्म के निर्माताओं के बीच कुछ तकनीकी और कागजी मसले हैं। जैसे ही ये मुद्दे सुलझेंगे, फिल्म पर काम आगे बढ़ जाएगा। परेश ने साफ संकेत दिया कि वह फिल्म के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

'बाबू भैया' के बिना नहीं चलेगा जादू

परेश रावल ने पहले भी कहा था कि 'बाबू भैया' का किरदार 'हेरा फेरी' की पहचान है। उनके मुताबिक, अगर यह किरदार फिल्म में नहीं हुआ तो दर्शकों को वो मजा नहीं आएगा और फिल्म को नुकसान उठाना पड़ सकता है। फैंस भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि 'हेरा फेरी 3' में एक बार फिर राजू (अक्षय कुमार), श्याम (सुनील शेट्टी) और बाबूराव (परेश रावल) की आइकॉनिक तिकड़ी साथ नजर आए।

'डॉन 3' पर ब्रेक, 'जी ले जरा' को आगे बढ़ाएंगे फरहान अख्तर

फरहान अख्तर की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'डॉन 3' पिछले काफी समय से चर्चा में है, लेकिन इसकी कास्टिंग को लेकर जारी असमंजस के बीच प्रोजेक्ट फिर से धीमा पड़ता नजर आ रहा है। रणवीर सिंह के फिल्म से अलग होने की खबरों के बाद अब यह फ्रैंचाइज़ी अनिश्चितता में घिर गई है। बीच में ऋतिक रोशन और शाहरुख खान के नामों को लेकर अटकलें भी लगीं, मगर फिलहाल कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में कहा जा रहा है कि फरहान अब अपना फोकस किसी दूसरी फिल्म पर शिफ्ट करने की तैयारी में हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, फरहान अख्तर अपनी ड्रीम रोड-ट्रिप फिल्म 'जी ले जरा' को दोबारा ट्रैक पर लाना चाहते हैं। यह प्रोजेक्ट लंबे समय से ठंडे बस्ते में था, लेकिन अब मेकर्स इसे आगे बढ़ाने के मूड में दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि फिल्म की स्क्रिप्ट पूरी तरह तैयार है और फरहान एक बार फिर प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट और कैटरीना कैफ से संपर्क में हैं, ताकि उनकी उपलब्ध तारीखों को लेकर बातचीत आगे बढ़ाई जा सके। दरअसल, 'जी ले जरा' की सबसे बड़ी चुनौती इसकी स्टार कास्ट की डेट्स का तालमेल बैठाना रहा है। तीनों अभिनेत्रियों के व्यस्त शेड्यूल के कारण पहले भी फिल्म की शूटिंग टलती रही है। सूत्रों का कहना है कि अगर तारीखें फाइनल हो जाती हैं, तो फिल्म की शूटिंग 2026 की दूसरी छमाही में शुरू हो सकती है। फरहान फिलहाल इसी दिशा में काम कर रहे हैं, जबकि 'डॉन 3' की कास्टिंग पर अंतिम फैसला होने में अभी वक्त लग सकता है।

'कोहरा 2' का ट्रेलर रिलीज

चर्चित क्राइम-थ्रिलर वेब सीरीज 'कोहरा' का दूसरा सीजन दर्शकों के मनोरंजन के लिए वापसी कर रहा है। इस बार सीरीज में अभिनेता बरुण सोबती के साथ अभिनेत्री मोना सिंह अहम किरदार में नजर आएंगी। दोनों मिलकर एक नए और खतरनाक केस का पर्दाफाश करेंगे और अपराधियों को सजा दिलाने की कोशिश करेंगे। मेकर्स ने हाल ही में 'कोहरा 2' का ट्रेलर रिलीज कर दिया है, जिसे देखने के बाद फैंस में रिलीज को लेकर जोश और उत्साह तेजी से बढ़ गया है। सीरीज का निर्देशन सुदीप शर्मा और फैसल रहमान ने मिलकर किया है। 'कोहरा 2' का ट्रेलर करीब 2 मिनट 3 सेकंड लंबा है, जिसमें शुरुआत एक लड़की की रहस्यमयी मौत से होती है। इस बार कहानी पंजाब के एक छोटे शहर की पृष्ठभूमि में सेट है, जहां क्राइम की गुत्थियों को सुलझाने के लिए कमांडिंग अधिकारी धनवंत कौर (मोना सिंह) को तैनात किया जाता है। उनके साथ सहायक सब-इंस्पेक्टर अमरपाल गरुंडी (बरुण सोबती) खतरों और रहस्यों से भरे मिशन पर कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। ट्रेलर में थ्रिल, सस्पेंस और अपराध की अनसुलझी परतों को शानदार तरीके से पेश किया गया है, जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखने का वादा करता है। 'कोहरा 2' नेटफ्लिक्स 11 फरवरी पर स्ट्रीम होगी। पहले सीजन की सफलता के बाद इस नए सीजन को भी फैंस का भरपूर प्यार मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। खासकर बरुण और मोना की नई जोड़ी और कहानी की रहस्यमयी गहराई के कारण। अगर आप थ्रिलर और क्राइम कहानी के शौकीन हैं, तो 'कोहरा 2' इस बार आपके लिए फरवरी का एक बड़ा वेब ट्रीट बनने जा रही है।

संसद में पेश हुआ देश का 'आर्थिक रिपोर्ट कार्ड'

एजेंसी । नई दिल्ली

.वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 29 जनवरी को देश का 'आर्थिक रिपोर्ट कार्ड' यानी इकोनॉमिक सर्वे लोकसभा में पेश किया। इस वित्तीय वर्ष में आयकर और जीएसटी में राहत, अप्रैल से लागू होने वाला नया आसान डायरेक्ट टैक्स कानून, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और दिवालिया ढांचे में बदलाव जैसे सुधार कार्य किए गए हैं। इस सर्वे में बताया गया है वित्त वर्ष 2026-2027 में जीडीपी ग्रोथ 6.8% से 7.2% की रेंज में रहने का अनुमान है। इसके अलावा महंगाई, खेती-किसानी की क्या हालत है और क्या आने वाले समय में नई नौकरियां बढ़ेंगी इसकी भी जानकारी सर्वे में दी गई है। वित्त मंत्री ने सदन में प्रश्नकाल समाप्त होते ही सदन में आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत की। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आवश्यक कागजात प्रस्तुत कराए। उन्होंने पिछले दिनों दिल्ली में आयोजित राष्ट्रमंडल देशों की संसद के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का भी उल्लेख किया। इसके बाद कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। सीतारमण रविवार, एक फरवरी को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए केंद्रीय बजट पेश करेंगी।

56.2 करोड़ लोगों के पास रोजगार का दावा

2026-2027 में जीडीपी ग्रोथ 7.2% तक रहने का अनुमान

नियंत्रण में रहेगी महंगाई दर

इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार, आरबीआई और आईएमएफ ने संकेत दिए हैं कि महंगाई दर नियंत्रण में रहेगी और यह 4% (2%) के निर्धारित लक्ष्य के दायरे में बनी रहेगी। अच्छी खरीफ और रबी फसलों के चलते, आरबीआई ने वित्त वर्ष 2026 के लिए महंगाई का अनुमान 2.6% से घटाकर 2% कर दिया है। वहीं, वित्त वर्ष 2027 की शुरुआती दो तिमाहियों में इसके 3.9% से 4% के बीच रहने की संभावना जताई गई है।

जीडीपी विकास दर में मजबूती

वैश्विक स्तर पर चल रहे तनाव और अस्थिरता के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार तेज बनी हुई है। सर्वे में अनुमान है कि वित्त वर्ष 2027 में जीडीपी ग्रोथ 6.8% से 7.2% के बीच रह सकती है। चालू वित्त वर्ष (FY26) के लिए यह अनुमान और भी उत्साहजनक है, जहाँ विकास दर 7.4% रहने की उम्मीद है, जो आरबीआई के 7.3% के अनुमान से भी अधिक है।

रोजगार और स्किल डेवलपमेंट

रोजगार के क्षेत्र में सुधार देखने को मिला है। वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में करीब 8.7 लाख नई नौकरियां पैदा हुई हैं, जिससे 15 वर्ष से अधिक आयु के 56.2 करोड़ लोग रोजगार से जुड़े हैं। टैक्स और श्रम सुधारों के साथ-साथ 'गिग इकोनॉमी' ने रोजगार बढ़ाने में मदद की है। अब सरकार का फोकस युवाओं के स्किल गैप को भरने के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग और रोजगार डेटा के लिए एक इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाने पर है।

कृषि क्षेत्र और किसान कल्याण

देश की आधी आबादी की आजीविका का आधार कृषि है, जिसमें वित्त वर्ष 2026 में 3.1% की वृद्धि की उम्मीद है। 2024-25 में 3,320 लाख टन के रिकॉर्ड अनाज उत्पादन ने महंगाई को काबू करने में अहम भूमिका निभाई है। सरकार अब केवल उत्पादन बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि उसका जोर किसानों की आय सुरक्षा, बेहतर स्टोरेज सुविधाओं और निर्यात के लिए नए बाजारों की तलाश पर है।

बुलेट ब्रीफ

- वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 7.4% और 2026-27 में 7.2% के रहने बीच का अनुमान
- बैंकों का ग्रॉस NPA घटकर 2.2% पर आया
- मार्च 2025 तक 55.02 करोड़ जन धन योजना खाते खुले
- कुल डीमैट खाते 21.6 करोड़ के पार, निवेशकों में 25% महिलाएं
- वैश्विक सामान निर्यात में भारत का हिस्सा बढ़कर 1.8% हुआ
- 701.4 अरब डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार 16 जनवरी 2026 तक
- भारत दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा (135.4 अरब डॉलर) पाने वाला देश बना रहा
- अप्रैल-दिसंबर 2025 के दौरान महंगाई दर औसत 1.7%
- रिकॉर्ड 35.77 करोड़ टन अनाज उत्पादन का अनुमान
- अब तक किसानों को 4.09 लाख करोड़ रुपये की सीधी वित्तीय सहायता
- 14 सेक्टरों में 2 लाख करोड़ रुपये का निवेश और 12.6 लाख नई नौकरियां
- 1.60 लाख करोड़ रुपये की 10 बड़ी परियोजनाओं पर काम शुरू
- हाई स्पीड कॉरिडोर बढ़कर 5,364 किमी हुए; एक साल में 3,500 किमी नई रेल लाइन
- भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एविएशन मार्केट, एयरपोर्ट्स की संख्या 164 हुई।
- 31 करोड़ से ज्यादा असंगठित मजदूरों का पंजीकरण

राजकोषीय घाटा और आर्थिक अनुशासन

केंद्र सरकार ने वित्तीय समझदारी दिखाते हुए राजकोषीय घाटे (Fiscal Deficit) को कम करने का लक्ष्य समय से पहले हासिल कर लिया है। वित्त वर्ष 2025 में यह जीडीपी का 4.8% रहा, जबकि वित्त वर्ष 2026 के लिए इसे 4.4% तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। घाटे में कमी आना एक मजबूत अर्थव्यवस्था का संकेत है, जिससे महंगाई को नियंत्रित रखने में भी मदद मिलती है।

विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति

वैश्विक मंदी की आहट के बीच भारत का विदेशी मुद्रा भंडार एक मजबूत स्थिति में पहुंच गया है। यह 2023-24 के 668 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2024-25 में 701 बिलियन डॉलर हो गया है। विदेशी मुद्रा का यह विशाल भंडार भारतीय अर्थव्यवस्था को बाहरी झटकों से बचाता है और डॉलर के मुकाबले रुपये को मजबूती प्रदान करता है।

निर्यात और नई व्यापार रणनीतियां

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में चुनौतियों और अमेरिका द्वारा 50% टैरिफ लगाए जाने के बावजूद, भारत का कुल निर्यात वित्त वर्ष 2025 में 825.3 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गया। अमेरिका पर निर्भरता कम करने के लिए भारत ने अपनी रणनीति बदली है और यूरोपीय संघ (EU), ब्रिटेन, न्यूजीलैंड और ओमान के साथ नए व्यापार समझौते किए हैं, जिससे भारतीय निर्यातकों के लिए नए बाजार खुले हैं।

40% गिग वर्कर्स की कमाई 15 हजार से कम

संसद में 29 जनवरी को पेश किए गए इकोनॉमिक सर्वे में गिग इकोनॉमी पर चिंता जताई गई है। सर्वे के मुताबिक, भारत में लगभग 40% गिग वर्कर्स यानी फूड डिलीवरी, क्विक कॉमर्स और अन्य प्लेटफॉर्म से जुड़े कर्मचारियों की महीने की कमाई 15 हजार रुपए से भी कम है। रिपोर्ट में सरकार से सिफारिश की गई है कि गिग वर्कर्स के लिए प्रति घंटा या प्रति टास्क के आधार पर 'मिनिमम अर्निंग' तय की जानी चाहिए। इसके अलावा, काम के इंतजार के दौरान लगने वाले समय के लिए भी पेमेंट दिए जाने का सुझाव सर्वे में दिया गया है। देश में गिग वर्कफोर्स बहुत तेजी से बढ़ रही है। वित्त वर्ष 2021 में गिग वर्कर्स की संख्या 77 लाख थी, जो वित्त वर्ष 2025 में 55% बढ़कर 1.2 करोड़ पहुंच गई है। फिलहाल कुल वर्कफोर्स में इनकी हिस्सेदारी 2% से ज्यादा है। अनुमान है कि साल 2029-30 तक नॉन-एग्रीकल्चर सेक्टर की कुल नौकरियों में गिग वर्क की हिस्सेदारी 6.7% हो जाएगी।

स्कूली शिक्षा 13 से बढ़ाकर 15 वर्ष करने की सलाह

आर्थिक सर्वेक्षण में एक अहम चेतावनी देते हुए भारत में अपेक्षित स्कूली शिक्षा अवधि को मौजूदा 13 से बढ़ाकर 15 वर्ष करने की सलाह दी गई है। सर्वे के मुताबिक, 2024 में भारत की करीब 27 फीसदी आबादी स्कूल जाने की उम्र (3–18 वर्ष) में थी। यही नहीं, 2047 तक भी यह हिस्सा 20 फीसदी से ज्यादा बना रहेगा। इसके बावजूद, भारत का शिक्षा सूचकांक अभी भी वैश्विक स्तर पर कमजोर बना हुआ है। इसकी सबसे बड़ी वजह है बच्चों की औसत अपेक्षित पढ़ाई के साल, जो भारत में कई विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाओं से कम हैं। भारत में अभी औसत अपेक्षित पढ़ाई 13 वर्ष है। जबकि चीन में 15.5 वर्ष, ब्राजील में 15.8 वर्ष, जापान में 15.5 वर्ष, जर्मनी में 17.3 वर्ष और अमेरिका में 15.9 वर्ष है। रूस में 13.2 और इंडोनेशिया में औसत अपेक्षित स्कूलिंग 13.3 वर्ष है। यह दोनों देश भारत से थोड़ा बेहतर हैं जबकि अन्य देशों की तुलना में भारत को लंबी छलांग लगाने की जरूरत है।

बैंक में पैसे जमा करने से बच रहे लोग

एक जमाना था जब लोग फ्यूचर सिक्योर करने और ब्याज के लिए अपनी बचत को बैंक में जमा कर देते थे लेकिन अब इसका पैटर्न बदल गया है। दरअसल, संसद में पेश किए गए 2025-26 के आर्थिक सर्वेक्षण में कुछ ऐसे आंकड़े पेश किए गए हैं जो लोगों के बदलते मिजाज को दिखाते है। इसके अनुसार भारतीय परिवारों की वित्तीय बचत में बैंक जमा का हिस्सा लगातार कम होता जा रहा है। इसके उलट, म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार में निवेश बढ़ता जा रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 (FY25) में वार्षिक वित्तीय बचत में बैंक जमा का हिस्सा मात्र 35% रह गया है, जो वित्त वर्ष 2012 के 58% से काफी कम है। हालांकि, इस गिरावट की भरपाई काफी हद तक म्यूचुअल फंड और शेयरों में निवेश में वृद्धि से हुई है, जिनका संयुक्त हिस्सा इसी अवधि में 1.8% से बढ़कर 15.2% हो गया है। सर्वेक्षण में आगे कहा गया है कि यह बदलाव व्यवस्थित निवेश योजनाओं (SIP) में योगदान में लगातार वृद्धि के साथ हुआ है। आंकड़े बताते हैं कि औसत मासिक SIP फ्लो सात गुना बढ़ गया है। यह वित्त वर्ष 2017 में 4,000 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2026 में 28,000 करोड़ या उससे अधिक हो गया है।

26000 किमी हाई स्पीड नेटवर्क का खाका पेश

आर्थिक सर्वेक्षण में सरकार ने बुनियादी ढांचे को वैश्विक स्तर पर ले जाने के लिए 2033 तक 26,000 किमी लंबा हाई-स्पीड कॉरिडोर नेटवर्क तैयार करने का खाका पेश किया है। वर्ष 2014 में यह नेटवर्क महज 550 किमी था, जो दिसंबर 2025 तक लगभग 875% बढ़कर 5,364 किमी हो चुका है। सरकार का उद्देश्य इस विस्तार के जरिए माल ढुलाई की गति को तेज करना और कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करना है। सरकार का मुख्य फोकस देश की लॉजिस्टिक्स (माल ढुलाई) लागत को घटाकर जीडीपी के एकल अंक (Single Digit) में लाना है। इसके लिए बंदरगाहों और औद्योगिक गलियारों को सीधे हाई-स्पीड राजमार्गों से जोड़ा जा रहा है। वर्तमान में 9,366 हाई-स्पीड कॉरिडोर परियोजनाएं (कुल लक्ष्य का 36%) निर्माण के अलग-अलग चरणों में हैं, जो भविष्य में सप्लाई चेन को और भी कुशल बनाएंगी।

मोटापे के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई

भारत में अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड (UPF) यानी जंक फूड की बढ़ती खपत और बच्चों में मोटापे के बढ़ते मामलों पर आर्थिक सर्वेक्षण ने गंभीर चिंता जताई है। सर्वेक्षण ने सुबह से देर रात तक ऐसे खाद्य पदार्थों के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया है। लोकसभा में पेश प्री-बजट दस्तावेज में कहा गया है कि भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड बाजारों में शामिल हो गया है, जो देश में स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों को बढ़ा रहा है। सर्वेक्षण के अनुसार, पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों में अधिक वजन की समस्या 2015-16 में 2.1 प्रतिशत थी, जो 2019-21 में बढ़कर 3.4 प्रतिशत हो गई। अनुमान है कि 2020 में भारत में करीब 3.3 करोड़ बच्चे मोटापे से ग्रस्त थे, जो 2035 तक बढ़कर 8.3 करोड़ हो सकते हैं।

राज्यों की लोकलुभावन घोषणाओं से चिंतित है सरकार

राज्य सरकारों की ओर से की गई लोकलुभावन घोषणाओं, लोगों के बैंक खाते में नकद रुपये भेजने पूंजीगत व्यय प्रभावित होने से उनका राजस्व घाटा बढ़ रहा है. संसद में गुरुवार को पेश आर्थिक समीक्षा में इस बात को लेकर चिंता जताई गई है .समीक्षा में जोर देते हुए कहा गया कि राज्य स्तर पर किसी भी प्रकार की राजकोषीय अनुशासनहीनता का सीधा असर देश की उधारी लागत पर पड़ता है. समीक्षा में यह भी कहा गया है कि कई राज्यों में बिना शर्त नकद अंतरण (यूसीटी) योजनाएं तेजी से बढ़ रही हैं और अब राज्य-स्तरीय कल्याणकारी खर्च का एक बड़ा हिस्सा बन गई हैं. विशेष रूप से महिलाओं के लिए चल रही इन योजनाओं पर वित्त वर्ष 2025-26 में लगभग 1.7 लाख करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है.

आरटीआई कानून की समीक्षा की सिफारिश

आर्थिक सर्वेक्षण में लगभग 20 साल पुराने सूचना का अधिकार (RTI) कानून, 2005 की समीक्षा की बात कही गई है। इसके साथ ही सर्वेक्षण में यह स्पष्ट कहा गया है कि इस कानून को केवल जिज्ञासा पूरी करने या सरकार को बाहरी निगरानी के माध्यम से नियंत्रित करने के लिए नहीं बल्कि सार्वजनिक कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही और लोकतंत्र में नागरिक भागीदारी बढ़ाने के लिए बनाया गया था। सर्वेक्षण में सुझाव दिया गया कि कानून में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। इनमें विचार-मंथन नोट्स, ड्राफ्ट टिप्पणियां और कार्य-पत्र तब तक खुलासे से सुरक्षित रखने की बात कही गई है जब तक वे अंतिम निर्णय का हिस्सा न बन जाएं। इसके अलावा, सेवा रिकॉर्ड, स्थानांतरण और गोपनीय कर्मचारी रिपोर्ट को ऐसे सामान्य RTI अनुरोधों से बचाने की सिफारिश की गई है जिनका सार्वजनिक हित से कमजोर संबंध हो।

भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक नज़र

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE